शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 3 ■ अंक 09 ■ जनवरी 2020 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 36

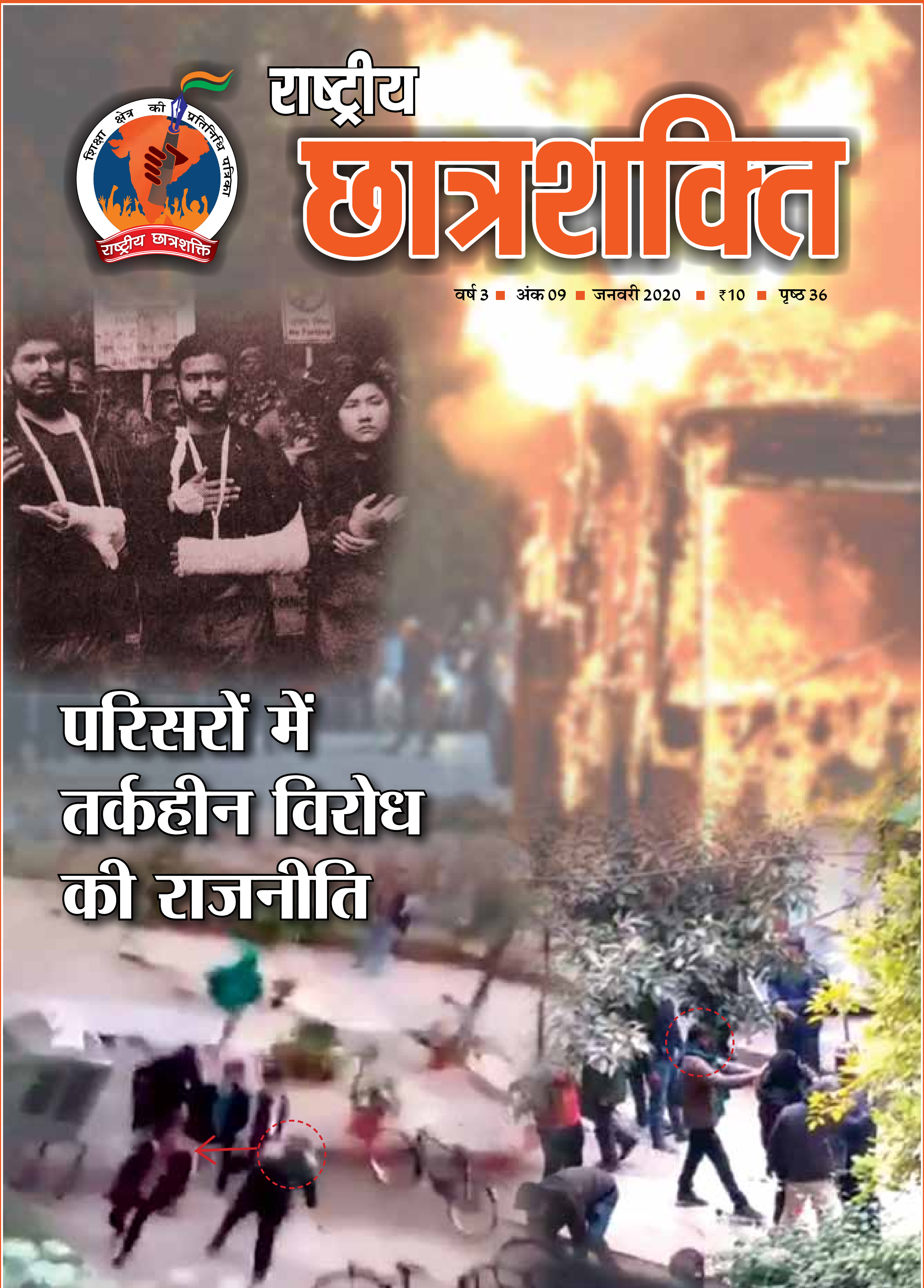

परिसरों में तर्कहीन विरोध की राजनीति

परिषद गतिविधियां

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट करते अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी

गोरखपुर : प्रतिभा सम्मान समारोह में पुरस्कार प्रदान करते सुपर 30 के आनंद कुमार, साथ में हैं अभाविप के अ.भा. रा. विवि कार्य प्रमुख श्रीहरि बोरिकर व अन्य

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 3, अंक 09
जनवरी, 2020

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

06 **जेएनयू: तर्कहीन विरोध की राजनीति का शिकार एक शिक्षा संस्थान**

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसक घटनाओं के बीच राजनीति उफान पर है। आरोप-प्रत्यारोपों का दौर जारी है।...

संपादकीय	04
SAVE JNU FROM LEFT – WING ATROCITY : ABVP	14
'सेवार्थ विद्यार्थी' के माध्यम से लोगों के दर्द को बांट रहे हैं परिषद कार्यकर्ता	15
ARTICLE / HISTORY OF VIOLENECE IN JNU	16
लेख / घुसपैठियों व शरणार्थियों में फर्क करना जरूरी	18
परमश्रद्धेय स्वामी पेजावर श्री स्वामी विश्वेश तीर्थ जी को विनम्र श्रद्धांजलि: अभाविप	19
लेख / नागरिकता कानून: कैंपस विद्रोह शहरी नक्सलवाद नहीं तो और क्या है?	20
'DEATH WARRANT' FOR THE MURDERERS AND RAPISTS IS REAL TRIBUTE TO NIRBHAYA : ABVP	23
अहमदाबाद: अभाविप कार्यालय पर एनएसयूआई का हमला	24
गोरखपुर: अभाविप द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन	25
भारतीय कला व संस्कृति के उत्थान के लिए विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण : निधि त्रिपाठी	26
नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन	28
प्रांतीय अधिवेशन / अनुशासित छात्र संगठन है विद्यार्थी परिषद: मनोहर लाल खट्टर	31
परिचर्चा / क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाली हिंसा के तार आपस में जुड़े हैं?	33

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

अनुच्छेद 370 में संशोधन, रामजन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भी संसद द्वारा पारित हो गया तो वे सभी शक्तियाँ बेचैन हो उठीं जिनके लिये देश में शांति और एकता का सशक्त होना दु:स्वप्न के समान है। ऐसे सभी विघ्नसंतोषी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध एकजुट हुए और उनके प्रभावक्षेत्र वाले विश्वविद्यालयों में हिंसा और ध्वंस का खेल शुरू हो गया।

यह करते हुए वे यह भूल गये कि बदलते भारत में पुराने टोटके आजमा कर देश को अपने पीछे खड़ा करना मुश्किल है। वे यह भी भूल गये कि देश ने अब शांति की कीमत पहचानी है और यह भी जान लिया है कि तेज विकास के लिये शांति-व्यवस्था पहली शर्त है। उसने अपने विवेक से काम लेना शुरू कर दिया है, क्षणिक भावुकता के बाद वह पुन: अपनी सहज गति में आ जाता है। यह किसी एक वर्ग नहीं, बल्कि पूरे देश की सोच में आये बदलाव का निष्कर्ष है।

हाल ही में जेएनयू में हुए घटनाक्रम को यदि इकलौती घटना अथवा अपवाद के रूप में देख रहे हैं तो गलती पर हैं। अप्रासंगिक होती अपनी स्थिति से हताश वामपंथी छात्र संगठनों ने 5 जनवरी को जिस संगठित हिंसा का प्रदर्शन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया, वह अलगाव की विचारधारा के लिये परिसर में स्थान और अवसर उपलब्ध कराने के दशकों पुराने अभ्यास का चरम बिन्दु था। अंतर केवल इतना है कि अतीत में इस परिसर में हथियार उठाने वालों का स्वागत हीरो की तरह किया जाता था, उनकी सभायें करायी जाती थीं, इस बार उनके समर्थकों ने खुद हथियार उठा लिये। 2016 के भारत तेरे टुकड़े होंगे और आजादी के नारे भूले नहीं होंगे। भूलना भी नहीं चाहिये।

निन्दनीय होते हुए भी यह घटना एक तरह से अच्छी ही है। वामपंथी दलों के लिये भी और देश के लिये भी। वे जिन 'आजादी' और 'अलगाव' के मुद्दों को विमर्श के केन्द्र में लाना चाहते थे, वह आ गया है। अकर्मण्य बौद्धिकता के धनी जो विद्वान शांति के उपदेश देते हुए टुकड़े-टुकड़े वाले नारों को कारपेट के नीचे ढ़क कर परोक्ष रूप से उनका ही हितसाधन करते थे, उन्हें भी इस घटना के बाद अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। अभाविप को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में उनके मीडिया में मौजूद शुभचिंतकों ने इस स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में देश के सामने

प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो इस पर देश का मिजाज भी समझने का मौका उन्हें मिलेगा, जो इस अतिवाद से क्षुब्ध हो चुका है।

दुर्भाग्य से देश की संसद में निर्वाचित होकर आये विपक्ष के सदस्य भी संविधान की व्यवस्था को नकारने पर उतारू हैं। कांग्रेस द्वारा एक दल के रूप में अपने द्वारा शासित राज्यों में नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं लागू करने की घोषणा या तो उनके बौद्धिक दिवालियपन की ओर इंगित करती है अथवा राजनैतिक आत्महत्या के उनके संकल्प की। उन्हें याद रखना चाहिये कि देश की जनता ने उन्हें संविधान के संरक्षण के लिये चुना है न कि उसके ध्वंस के लिये। साथ ही उन्हें यह भी याद रखना होगा कि जिस जनता ने उन्हें चुन कर संसद में भेजा है उसने ही मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है। उनके संवैधानिक अधिकार को चुनौती देने और हिंसा और आगजनी के बल पर इसे रोकने से पहले इसके संवैधानिक परिणामों का आकलन कर लेना उनके लिये अच्छा होगा। नये घटना क्रम में देश के 200 से अधिक शिक्षाविदों ने 12 जनवरी को प्रधानमंत्री को संबोधित एक सार्वजनिक पत्र में देश में बिगड़ते अकादमिक माहौल के लिये वामपंथी कार्यकर्ताओं के एक छोटे समूह की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। इन शिक्षाविदों ने जेएनयू सहित देश भर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है ताकि जल्द से जल्द परिसरों में सौहार्द्रपूर्ण माहौल बहाल हो सके। निश्चय ही यह अभियान आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा और परिसरों में अलगाव और आतंक के समर्थन को लेकर एक निर्णायक राष्ट्रीय विमर्श को जन्म देगा।

अभाविप के कार्यकर्ता अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को प्रकट करते हुए राष्ट्रीयता को इस विमर्श के केन्द्र में स्थापित करने के लिये यथासंभव प्रयत्न करेंगे। काल की अपनी गति होती है। परिषद के कार्यकर्ताओं की वर्तमान पीढ़ी के सम्मुख यह अवसर अनायास ही आ उपस्थित हुआ है जिसमें से वैचारिक रूप से विजयी होकर निकलने की चुनौती हमारे सम्मुख है।

शुभकामना सहित,

आपका

संपादक

जेएनयू: तर्कहीन विरोध की राजनीति का शिकार एक शिक्षा संस्थान

| आशुतोष भटनागर |

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसक घटनाओं के बीच राजनीति उफान पर है। आरोप-प्रत्यारोपों का दौर जारी है। मीडिया में जांच से पहले निर्णय देने का सिलसिला जारी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अराजकता के चलते अपनी प्रतिष्ठा के सबसे निचले पायदान पर है।

देश में आज एक बड़ा वर्ग है जो देश की वर्तमान राजनैतिक दिशा से असहमत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह असहमति उसका अधिकार है। लेकिन इसे प्रकट करने के लिये यह विपक्षी दल जो तौर-तरीके अपना रहे हैं वह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हैं। इनके मन में यह छटपटाहट थी कि तीन तलाक के विरुद्ध कानून बन गया, अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद भी देश में शांति बनी रही और अयोध्या पर फैसले का भी व्यापक विरोध नहीं हुआ। नागरिकता संशोधन कानून को इन्होंने अपने लिये एक अवसर के रूप में लिया तथा मुस्लिम समुदाय में भ्रम और डर पैदा कर देश में आग लगाने की रणनीति बनाई गई।

अराजक राजनीति के देशव्यापी गठजोड़ के हरावल दस्ते के रूप में अपनी पहचान बना चुके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय आदि से इन आंदोलनों की शुरुआत होती है और देश के अन्य संस्थानों के छात्रों को छात्र एकता के नाम पर इसमें जुड़ने के लिये प्रेरित

किया जाता है।

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में जामिया में भड़के आंदोलन के दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि पुलिस ने स्वयं बसों में आग लगाई। एक वीडियो भी जारी किया, जबकि बाद में इस बात की पुष्टि हो गई है कि वह आग बुझा रहे थे। यह अफवाह फैलाई गयी कि जामिया में पुलिस गोली से छात्र मारे गए हैं। इसके विरुद्ध आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय को घेरने का आह्वान करने वाला सघन अभियान सोशल मीडिया पर चलाया गया। देखते-ही देखते हजारों छात्र और शिक्षक वहाँ इकट्ठे हो गये।

प्रदर्शनकारी गांधी, अंबेडकर और संविधान की दुहाई दे रहे हैं किंतु दुर्भाग्य से उनके दर्शन से इन आंदोलनकारियों का कोई लेना-देना नहीं है। गांधी की दुहाई देने वाले हिंसा में लिप्त हैं और अंबेडकर का नाम लेने वाले संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संगठित हिंसा का जो दृश्य दिखा वह विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार है।

सच पूछें तो अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद से ही विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ विरोध अब तक थम नहीं सका है। वामपंथी दल मौका तलाश रहे थे कि बड़ी संख्या में तटस्थ विद्यार्थियों को अपने पक्ष में लामबंद कर सकें। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बीस साल बाद की गयी फीसवृद्धि ने उन्हें यह अवसर दे दिया। सभी छात्र संगठनों ने इसका संयुक्त विरोध किया। लेकिन वाम दलों से जुड़े छात्र संगठन जब इस जुटान का राजनैतिक लाभ नागरिकता संशोधन विधेयक के विरुद्ध केन्द्र के विरोध में करने की कोशिश करने लगे तो सामान्य छात्रों ने अपने आपको इस आन्दोलन से अलग कर लिया।

आन्दोलन को छात्रों का अपेक्षित समर्थन न मिलते देख यह संगठन अराजकता पर उतर आये और छात्रसंघ ने इसकी अगुआई संभाल ली। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस वृद्धि में भारी कमी किये जाने के बाद आम विद्यार्थी इस आंदोलन से दूर होने लगा था। किन्तु वामदलों ने इसे समाप्त करने के बजाय परीक्षाओं के बहिष्कार की अपील की और जो विद्यार्थी अथवा शिक्षक परीक्षाओं में भाग ले रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। कैंपस से बाहर रहने वाले छात्रों को आने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इससे पहले कक्षाओं के बहिष्कार के नाम पर एक महिला प्राध्यापक को 32 घंटे तक क्लासरूम में बंधक बना कर जेएनयू की परंपराओं को कलंकित किया गया था। एक अन्य हॉस्टल वार्डन महिला प्राध्यापक को उनके घर में ही घंटों बंधक बनाये रखा गया।

परिसर में तनाव तब बढ़ा जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नये सेमेस्टर में प्रवेश लेने आने वाले छात्रों की सहायता करने और वाम दलों ने उन्हें प्रवेश न लेने देने की कोशिश की। इसमें वामदलों को असफलता हाथ लगी और अधिकांश छात्रों ने प्रवेश ले लिया। अपने आंदोलन को पिटता देख खीझे वाम दलों ने तीन दिन पहले विश्वविद्यालय के सर्वर रूम को तहस-नहस कर प्रवेश प्रक्रिया को तकनीकी रूप से असंभव बना दिया। खबर यह भी है कि इसके लिये उन्होंने सर्वर रूम की देख-भाल करने वाले कर्मचारी को धमकाया।

आम विद्यार्थी इससे आक्रोशित था और आंदोलनकारी छात्र संगठन हताश। नतीजा 5 जनवरी को हिंसा की उस घटना के रूप में सामने आया जिसके तमाम वीडियो फुटेज टीवी स्क्रीन पर पूरे देश ने देखे। घटना के तुरंत बाद कुछ चैनलों पर एकतरफा रिपोर्टिंग का दौर शुरू हो गया। गैर-भाजपा राजनैतिक दलों के नेता जितनी फुर्ती से जेएनयू और एम्स पहुंचे उससे यह संदेह होता है कि सब कुछ सुनियोजित था। इस बीच एएमयू, जामिया, जादवपुर आदि विश्वविद्यालयों में भी आंदोलन शुरू होने की खबर है। हांलाकि यह घटना के विरोध में नहीं बल्कि वामपंथी दलों के समर्थन में है।

अपने ऊपर मीडिया में लगाये जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गत छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे मनीष जांगिड़ ने बताया कि छात्रावास में प्रवेश करने वाले हमलावर नाम ले-ले कर परिषद कार्यकर्ताओं को खोज रहे थे। वे जिस कमरे में चार कार्यकर्ताओं के साथ छिपे थे उसमें उन्होंने दरवाजा तोड़ कर प्रवेश किया और बुरी तरह घायल किया। मनीष के हाथ में दो फ्रेक्चर हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख कार्यकर्ता घायल होने के कारण घटना के तुरंत बाद अपना पक्ष रखने में असफल रहे।

यह जांच का विषय है कि हमलावर नकाबपोश कहां से और किसके बुलावे पर परिसर में आये। सुरक्षा व्यवस्था को धता बता कर इतनी बड़ी संख्या में वे परिसर में कैसे प्रवेश कर सके, इसकी जांच भी जरूरी है। लेकिन जांच से पहले ही मीडिया में निर्णय सुना देने और एक स्थानीय घटना में प्रधानमंत्री-गृहमंत्री के नाम घसीटने की प्रतियोगिता जिस प्रकार प्रारंभ हो गयी है उससे लगता है कि शिक्षा के एक संस्थान की गरिमा की चिन्ता कम और राजनैतिक बढ़त कायम करने की कोशिश ज्यादा है। जेएनयू जैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान आज तर्कहीन विरोध की राजनीति का शिकार हो अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फीस वृद्धि की जिस मांग की आड़ में यह आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भारी कमी की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा बहुत पहले की जा चुकी है। नये प्रवेश के समय जो फीस छात्रों से ली गयी है वह देश के अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कम है। फिर भी इसकी आड़ में आंदोलन को जारी रखना और प्रवेश तथा शिक्षणकार्य को बाधित करना यह आंदोलनकारियों की मंशा पर सवाल खड़े करता है।

उल्लेखनीय है कि फीस वृद्धि की जिस मांग की आड़ में यह आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भारी कमी की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा बहुत पहले की जा चुकी है। नये प्रवेश के समय जो फीस छात्रों से ली गयी है वह देश के अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कम है। फिर भी इसकी आड़ में आंदोलन को जारी रखना और प्रवेश तथा शिक्षणकार्य को बाधित करना यह आंदोलनकारियों की मंशा पर सवाल खड़े करता है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इसमें फीसवृद्धि और उसके विरुद्ध आंदोलन, यह एक स्थानीय समस्या है जिसका समाधान वहां के विद्यार्थियों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन को मिल कर ढूँढना है। इससे इतर विभिन्न राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में निरूपित करने की कोशिश की और फीसवृद्धि को केन्द्र सरकार द्वारा छात्रों के दमन के रूप में प्रस्तुत किया।

इस दौर में देश विरोधी बयानबाजी को प्रगतिशीलता के प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। इसलिये अब केवल राजनेता ही नहीं बल्कि सेलेब्रिटी कहलाने वाले अनेक लोग भी ऐसे मामलों में बिना तथ्यों की पड़ताल किये कूद पड़ते हैं। चर्चा में बने रहने की इच्छा इससे जरूर पूरी होती है। फिल्म 'छपाक' के प्रचार के लिये दिल्ली आयी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 'पीडित' वामपंथी छात्रों के बीच जेएनयू जा पहुंचीं। उनके इस साहस की सराहना करने के लिये शबाना आजमी, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, महेश भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, सयानी गुप्ता, अपर्णा सेन आदि कलाकार आगे आये और उन्हें हीरो बताते हुए उनके साहस को सलाम करने की बात की। दीपिका के इस कारनामे के तुरंत बाद कांग्रेस शासित राज्यों में उनकी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर भाजपा से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी आलोचना के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता ने नरेन्द्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि वे 'भारत की आत्मा' को कुचलना बंद करें।

निष्कर्ष यह कि एक स्थानीय समस्या को राष्ट्रहित का मुद्दा बना कर प्रस्तुत करना और उसे जनता द्वारा बहुमत देकर सत्ता सौंपने के सत्य को नकार कर तर्कहीन और निराधार आरोपों से घेरकर उसका मानभंग करने के कुत्सित प्रयास के रूप में इस पूरे प्रकरण को देखा जा सकता है। वामपंथ के वैचारिक टापू के रूप में उत्तर भारत के अकेले केन्द्र जेएनयू में जारी भारत विरोधी गतिविधियों की श्रृंखला में यह नवीनतम कड़ी है। इसे एक अकेली घटना के रूप में नहीं बल्कि श्रृंखला के रूप में ही समझने और मूल्यांकन करने की जरूरत है। ■

उपद्रव के दोषी

जेएनयू में 5 जनवरी को वैचारिक मतभेदों ने हिंसा का रूप धारण कर लिया। दो समूहों के बीच संघर्ष में अनेकों छात्र घायल हुए और परिसर में तनाव चरम पर पहुंच गया। पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति पाने के बाद जब परिसर में प्रवेश किया तब तक सभी हमलावर नकाबपोश गायब हो चुके थे। घायलों को एम्स और सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी।

इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से समझने की जरूरत है। फीस वृद्धि के विरुद्ध छात्र आन्दोलन करते हैं जिसमें दक्षिण-वाम सभी संगठनों के लोग शामिल होते हैं। आन्दोलन के एक ऊंचाई हासिल करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन झुकता है और फीस में पर्याप्त कमी करता है। इसके बाद सामान्य छात्र आन्दोलन से दूर हो जाते हैं। वाम संगठन फीस वृद्धि को पूरी तरह वापस लेने तक आंदोलन न रुकने की बात कहते हैं और आंदोलन के परिणामस्वरुप छात्रों में जगी संवेदना को नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में मोड़ने की कोशिश करते हैं।

यह छात्र संगठन पिछले सेमेस्टर में परीक्षाओं के वहिष्कार की बात करते हैं किन्तु अधिकांश छात्र उसमें भाग लेते हैं। इसके बाद बारी आती है नये सेमेस्टर में प्रवेश की। 3300 छात्र बढ़ी हुई फीस के साथ प्रवेश ले लेते हैं और आंदोलनकारियों को लगता है कि वे लड़ाई हार गये हैं। इसके लिये वे अभाविप को विशेष रूप से दोषी मानते हैं और 5 जनवरी को हताशा के चरम पर पहुंचने पर उनसे शारीरिक रूप से निपटने की योजना बनाते हैं।

अपनी योजना को अंजाम देते हुए छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष गीता कुमारी, वर्तमान अध्यक्ष आइशी घोष और महासचिव सतीश यादव के नेतृत्व में चेहरों पर नकाब बाँध कर पेरियार हॉस्टल पर धावा बोलते हैं जहाँ अभाविप के अनेक प्रमुख कार्यकर्ता रहते हैं। पेरियार में रहने वाला उनका काडर अभाविप कार्यकर्ताओं के कमरों की निशानदेही करता है जिसके खिड़की दरवाजे तोड़ कर वे परिषद कार्यकर्ताओं को अपनी भाषा में सबक सिखाते हैं। यह घटना शाम पाँच बजे घटती है। अभाविप के कार्यकर्ता अपने घायल साथियों को लेकर सफदरजंग अस्पताल और एम्स जाते हैं दूसरी ओर घटना को अंजाम देने के बाद यह नकाबपोश हमलावर और उनका नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी साबरमती छात्रावास पहुंच कर 'पीस मीटिंग' में शामिल हो जाते हैं।

यहाँ तक पूरा घटनाक्रम एकतरफा है। वामपंथी

दलों के कैडर ने अभाविप के कार्यकर्ताओं को चुन-चुन कर निशाना बनाया है। इस घटना के वीडियो फुटेज मौजूद हैं जिनकी प्रारंभिक तौर पर पुष्टि होने के बाद पुलिस ने इन्हें नोटिस भी दिया है। इसके बावजूद देखते ही देखते विपक्ष के तमाम राजनेता और मीडिया का एक धड़ा अभाविप और उसके बहाने सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। राजनीति के संरक्षण में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं केरल और पश्चिम बंगाल में ही सुनी जाती थी, दिल्ली ने इसका अनुभव पहली बार किया है। ■

मीडिया की भूमिका

कुछ पत्रकार और टेलीविजन चैनल आंदोलनकारियों से भी ज्यादा उत्तेजित थे। जेएनयू के घटनाक्रम के बाद तो उनकी भावनाएं सारे बाँध तोड़ कर बहने लगीं। एक एंकर ने तो छात्रों से पहले कुलपति के नाकारा होने की बात कहते हुए उनके पद पर बने रहने पर सवाल उठाया और हटाये जाने की माँग की। यह सभी लोग साबरमती पर हुई घटना को तो बार-बार दोहराते और मोदी-शाह पर सवाल उछालते नजर आये किन्तु पेरियार पर हुए संगठित हमले की चर्चा से बचते दिखे।

अभाविप के जो कार्यकर्ता दो घंटे पहले एम्स पहुंच चुके थे उन तक पहुंचने की फुरसत उन्हें तभी मिली जब आइशी घोष वहाँ पहुंची। प्रियंका गाँधी घायलों के लिये कम्बल लेकर पहुंची और गलती से उन्होंने इसे अभाविप के घायलों को भी दे दिया। लेकिन जब उन्हें यह संज्ञान में लाया गया तो उनके निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ता कंबल छीन ले गये। इस घटना में मीडिया को खबर नहीं दिखी।

एक चैनल ने तीन दिन बाद एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें वामपंथी कार्यकर्ताओं ने घटनाक्रम में अपना हाथ होना कबूल किया। लेकिन यह ऑपरेशन तब तक सेकुलरिज्म की कसौटी पर नहीं खरा उतरता था जब तक कि अभाविप के कार्यकर्ता उसमें न फंसे। नतीजे में ऐसे छात्रों की खोज की और उन्हें डींग हाँकने वाले दो चेहरे मिल भी गये जिन्होंने अपने आप को परिषद का कार्यकर्ता बताया। वे इससे पहले भी एक दो जुलूसों में परिषद के समर्थन में नारे लगाते दिख रहे थे और मीडिया के लिये इतना काफी था।

रिपोर्टिंग जिस तरह से हुई वह अपने आप में भ्रम उत्पन्न करने वाली है। घटों टीवी के सामने गुजार कर भी की दर्शक यह नहीं समझ सका कि यह एक घटना नहीं बल्कि दो अलग-अलग जगह हुई घटनाओ का मीडिया घालमेल है। एक घटना पेरियार हॉस्टल में हुई, जो अभाविप कार्यकर्ताओं पर सोचा-समझा संगठित हमला था जिसका नेतृत्व वामपंथी छात्र संगठनों के अनुभवी नेता और छात्रसंघ के जिम्मेदार पदाधिकारी कर रहे थे। इन सभी नेताओं के वीडियो उपलब्ध हैं। दूसरी ओर साबरमती हॉस्टल पर हुई घटना पहली घटना की त्वरित, अनियोजित प्रतिक्रिया थी जिसमें परिषद का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी शामिल नहीं था। चैनल के पास जिनका स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज

मौजूद है वे भी प्रथम वर्ष के छात्र हैं जिन्होंने इसी वर्ष परिस,र में प्रवेश किया है और यहाँ की परंपराओं को सीखने के दौर से गुजर ही रहे हैं। स्टिंग के दौरान जिस प्रकार यह दोनों छात्र दावे कर रहे हैं कि वे पूरी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, सारे सीनियर उनकी बनायी योजना के अनुसार काम कर रहे थ, उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे, पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड भी उसमें शामिल थे और उनके ही कहने पर उन्होंने लाइट गुल की थी, यह हास्यास्पद ही है। स्टिंग देख कर ऐसा लगता है कि पूरा जेएनयू इन नौसिखियों के ही इशारे पर नाच रहा था।

निष्पक्ष रूप से विष्लेषण करें तो न इन दोनों घटनाओं की तुलना की जा सकती है और न ही स्टिंग ऑपरेशन में फंसे कार्यकर्ताओं की। अपने-अपने संगठनों में उनकी हैसियत में जमीन-आसमान का फर्क है, किन्तु मीडिया इसे नजरअंदाज कर दोनों पक्षों को बराबर का अपराधी ठहराने और इस बहाने वामदलों के संगठित अपराध को हल्का करके दिखाने की कोशिश का जाने-अनजाने हिस्सा बन गया है।

यही भूमिका पुलिस के परिसर में प्रवेश को लेकर भी रही। जामिया में उपद्रवियों का पीछा करते हुए जब पुलिस बिना अनुमति लिये परिसर में प्रवेश कर गयी तो इसके लिये उसे पानी पीकर कोसा गया। इससे सबक लेते हुए जब जेएनयू में पुलिस ने बिना अनुमति प्रवेश नहीं किया तो भी उसकी आलोचना हुई।

इस सबसे बड़ा दाग मीडिया पर यह रहेगा कि जब इस घटनाक्रम से काफी पहले कक्षाओं और परीक्षाओं के वहिष्कार के नाम पर इन्ही अराजकतावादियों ने एक महिला प्रोफेसर को 32 घंटों तक क्लास रूम में बंधक बना कर रखा तो इसकी चर्चा मीडिया में नहीं की गयी। एक अन्य महिला वार्डन के घर को जब आधी रात में घेरा गया और घंटों उनको बंधक बनाया गया तो भी चुप्पी नहीं टूटी। इस मौन समर्थन का ही नतीजा था कि अराजक भीड़ ने माना कि वे कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं और मीडिया का समर्थन उसे जारी रहेगा। इस दोहरे रवैये ने जेएनयू के साथ ही मीडिया की तटस्थ छवि पर भी सवाल खड़े किये हैं जिनसे उबरने के लिये मीडिया को मेहनत करनी पड़ेगी। ■

अफवाहों का बाजार

हाल के दिनों में पराजित विपक्ष सारी मर्यादा और सिद्धांतों को ताक पर रख कर सड़कों पर अराजकता फैलाता नजर आ रहा है। जामिया विश्वविद्यालय के बाहर आंदोलनकारी छात्र और उनके साथ जुटी अन्य लोगों की भीड़ ने हिंसा और आगजनी शुरू कर दी। इसे नियंत्रित करने के लिये पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को खदेड़ा। इसी भीड़ के कुछ लोग जामिया विश्वविद्यालय परिसर के भीतर से पुलिस पर पथराव करने लगे। पुलिस ने परिसर में प्रवेश कर उन्हें भी नियंत्रित किया। जिसमें कुछ छात्रों को चोटें आयीं।

पेशेवर नेताओं ने इसे मुद्दा बनाया और सोशल मीडिया का सहारा लेकर आईटीओ स्थिति पुलिस मुख्यालय घेरने की अपील की। पूरी दिल्ली से हजारों लोग, जिनमें गैर-छात्र भी बड़ी मात्रा में थे, जा पहुंचे और रास्ते जाम कर दिये। सोशल मीडिया पर घटना को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। कुछ संदेश तो छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की अफवाह भी फैला रहे थे, जबकि पुलिस द्वारा गोली चलायी ही नहीं गयी। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका, जो छात्रों के समर्थन में वहाँ मौजूद थीं, ने टीवी स्क्रीन पर पुलिस गोली से छात्रों के मारे जाने का दावा किया और जब पत्रकार ने उनसे इसकी पुष्टि करने की बात कही ते वे इससे मुकर गयीं।

उपद्रवियों और नकाबपोशों की संख्या को लेकर भी बड़े-बड़े दावे किये गये। किसी भी वीडियो क्लिप में उनकी संख्या 30-40 से ज्यादा नहीं दिखा रही लेकिन चैनलों में उनकी संख्या 300-400 तक पहुंच चुकी थी। ■

5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ घटनाक्रम पहला नहीं है। इससे पहले भी परिसर के अंदर आपत्तिजनक गतिविधियों के समाचार मिलते रहे हैं, जिनका चरम बिन्दु इस हिंसक संघर्ष के रूप में सामने आया है। इसके कुछ उदाहरण निम्नवत है : –

आतंकियो के साथ संबध

10 अप्रैल 1991

- दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए पाकिस्तान, ब्रिटेन के तत्वों के इशारे पर काम करने वाले यूके, कनाडा, यूएसए और नेपाल के लोगों को शामिल किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के एक शीर्ष रैंकिंग ऑपरेटर अशफाक हुसैन लोन एवं मानवाधिकार की आड़ में काम करने वाले करने वाले जेएनयू के छात्र सहाबुद्दीन गोरी को गिरफ्तार किया था।

15 नवंबर, 1995

- एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जहाँ भारत के एक और विभाजन की गई थी।

देश विरोधी गतिविधियां

7 फरवरी, 1996

- जर्मन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर बादल घन चक्रवर्ती ने 7 फरवरी 1996 को जेएनयू के कुलसचिव को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जेएनयू विश्वविद्यालय में चल रही पाकिस्तान परस्त देशद्रोही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया।

पाकिस्तान परस्त तत्व

अप्रैल 2000

- 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय जीत के उत्साह को फीका करने के लिए जेएनयू परिसर में भारत - पाक मुशायरा आयोजित किया गया था।
- पाकिस्तानी कवि फहमीदा रियाज ने परमाणु विस्फोटों पर एक कविता का पाठ किया।
- जेएनयू में अपने दोस्तें से मिलने गये सेना के दो मेजर (सिविलियन ड्रेस में) पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के गवाह थे।
- पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की ऊंचाइयों पर लड़ने वाले इन दोनो सैन्य अधिकारियों ने जब इस तरह के नारों का प्रतिकार किया तो देश विरोधी तत्वों की भीड़ ने उनके साथ मारपीट की।

CRPF जवानों की शहादत पर जश्न

- 9 अप्रैल, 2010 को डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 67 जवानों के शहादत के जश्न में कार्यक्रम आयोजित किये, जिसमें वे लोग भारत 'भारत मुर्दाबाद', माओवाद जिंदाबाद 'जैसे नारे लगा रहे थे।

बीफ एंड पोर्क फेस्टिवल

सितंबर 2012

- बीफ और पोर्क फेस्टिवल के लिए जेएनयू में एक समूह द्वारा बीफ और पोर्क फेस्टिवल का आयोजन किया गया था ताकि खाने के अधिकार का जश्न मनाया जा सके। हालांकि अभाविप और कई अन्य राष्ट्रीय विचार रखने वालों संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि गाय हिंदूओ की माता के समान है, गोमांस के सेवन से धार्मिक भावनाएं आहत होगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ले जाया गया, न्यायालय ने इस तरह के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

महिषासुर दिवस

अक्टूबर 2014

- 'द हिन्दू' की एक रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय पिछड़े छात्र मंच से संबंधित छात्रों के एक समूह ने कथित तौर पर माता दुर्गा के आपत्तिजनक पर्चे वितरित किए और महिषासुर शहादत दिवस मनाने

की योजना बनाई जिसका विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया क्योंकि यह हिंदुओं को भावना को आहत करने वाली तस्वीर थी।

किस ऑफ लव

नवंबर 2014

- 'पत्रिका' की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 200 जेएनयू छात्रों के द्वारा 'किस ऑफ लव' अभियान के समर्थन में दिल्ली में रा. स्व.संघ के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किये। यह आयोजन राष्ट्रवादी संगठन के नैतिक मूल्यों के खिलाफ आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) के छात्र कार्यकर्ता शामिल थे।

कश्मीर की स्वतंत्रता

फरवरी 2015

- डीएसयू ने जेएनयू में भारत विरोधी बैठक आयोजित की।
- उमर खालिद कार्यक्रम आयोजकों में से एक था
- वक्ताओं की टोली में एक एसएआर गिलानी भी थे, जो एक कश्मीरी शिक्षक थे, जिनका नाम भारतीय संसद पर हमले में दिया गया था।
- अज़ादी (स्वतंत्रता) हमारी नियति है, जिसे हम एक दिन हासिल करेंगे कहने वाले एस.ए.आर. गिलानी, जो राजनीतिक कैदियों की रिहाई समिति के अध्यक्ष भी हैं।
- दिल्ली के एक कश्मीरी लेखक आरिफ अयाज पार्रे और एक लेखक व कवि उज़्मा फलक ने भी इस अवसर पर बात की।
- कश्मीर नारों की आजादी के साथ जुलूस निकाला गया

इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल

जनवरी 2016

- कश्मीरी अलगाववादी समर्थक छात्रों द्वारा इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल के दौरान कश्मीर का अलग स्टॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि यह अंतर - राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था। कश्मीर के नाम से अलग स्टॉल लगाने के प्रस्ताव का विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया फलस्वरूप कश्मीरी फूड काउंटर की बुकिंग रद्द करनी पड़ी। परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि कश्मीर कोई अलग देश नहीं है जो आपलोग अलग स्टॉल लगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं परिषद के कार्यकर्ताओं ने आयोजकों को ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी।

अफ़ज़ल के पक्ष में विरोध

9 फरवरी, 2016

- साबरमती ढाबा में पूर्व में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (डीएसयू) के 10 छात्रों द्वारा, अफजल गुरु और अलगाववादी नेता मकबूल भट को फांसी दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया था।
- अफ़ज़ल गुरु को संसद पर 2001 के हमले में उनकी भूमिका के लिए 9 फरवरी, 2013 को फांसी दी गई थी। मुहम्मद मकबूल बट को 11 फरवरी, 1984 को फांसी दी गई थी।
- कश्मीर की आज़ादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी जैसे भारत विरोधी नारे लगाए गए।

आयशा किदवई

- 2016 में किदवई ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) का नेतृत्व किया। जब छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था

2 मार्च, 2017

- 'स्वतंत्रता के लिए कश्मीर-स्वतंत्र फिलिस्तीन के स्वतंत्रता के अधिकार' शीर्षक वाला एक पुराना पोस्टर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की दीवार पर सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा देखा गया था।

ये प्रोफेसर कश्मीर और उत्तर-पूर्व में अलगाववाद के प्रचार के लिए जेएनयू और विश्वविद्यालय में वरिष्ठ शिक्षकों की अपनी प्रतिष्ठित स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को वैध बनाने और तर्कसंगत बनाने के लिए, सेमिनार, व्याख्यान आयोजित करके नफरत और देश विरोधी भावनाओं की आग भड़का रहे हैं। बिना किसी भय के जेएनयू में कई वर्षों से पर्चे, पोस्टर, प्रकाशन और नुक्कड़ नाटक, रैलियाँ, धरने, धरने, भूख हड़ताल और हड़तालें जारी हैं। ■

नहीं लिया जा रहा है यूटिलिटी और सर्विस चार्ज : जेएनयू प्रशासन

हॉस्टल फीस को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ किया है कि विंटर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन 2020 के दौरान स्टूडेंट्स से यूटिलिटी चार्ज और सर्विस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। गुरुवार को जेएनयू स्टूडेंट्स और टीचर्स की ओर से निकाले गए सिटीजंस मार्च और एचआरडी मिनिस्ट्री सेक्रेटरी से हुई बातचीत के बाद प्रशासन ने बयान जारी किया। देर रात जेएनयू रजिस्ट्रार डॉ प्रमोद कुमार ने सर्कुलर जारी कर कहा की 10 और 11 दिसंबर को एचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में हुई चर्चा के मुताबिक सर्विस चार्ज और यूटिलिटी चार्ज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन देगी। रजिस्ट्रार ने कहा है कि हॉस्टल के इन दोनों चार्ज देने के लिए यूजीसी से फंड देने के लिए पहले ही कहा जा चुका है। यूजीसी में उचित स्तर पर मामले पर बातचीत चल रही है।

स्टूडेंट्स की ओर से मिनिस्ट्री में फीस बढ़ोतरी को पूरी तरह से वापस लेने और वीसी को हटाने की मांग रखी गई जिस पर सेक्रेटरी ने कहा कि वो वीसी से संशोधित फीस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। ■

Save JNU from Left - Wing Atrocity : ABVP

ABVP fervently appeals to the larger student-community to extend its support to the resistance against left-radicalism. Up-to-the-minute developments have put the spotlight squarely on the unsettling role played by the JNUSU President in actively facilitating the illegal ingress of saboteurs into the JNU campus.

ABVP activists have been distinctively targeted by way of indiscriminate stone-pelting and cold-blooded caning, leaving twenty-five of them critically wounded. The agitprops have miserably failed to even remotely establish ABVP's association with the violence. On the contrary, most of the phoney defamatory materials insinuating ABVP's involvement have been successfully traced back to spurious WhatsApp groups, created and managed by the Indian National Congress. Such mischief must be unequivocally condemned by every right-thinking citizen.

To all intents and purposes, the Left has declared a war against reason, progress, and education. Even the nonpartisan and no belligerent students are being coerced by the leftist-louts to sink to their knees in supplication. Their academic progress is being indubitably threatened.

While the original perpetrators of violence have given an archetypal spin to this sordid episode of savagery, the primary victims are being wrongfully and dishonestly represented as the aggressors. It must be recapitulated that it was ABVP that had made the first request for Police Emergency Services; since being woefully outnumbered, it had more to lose in an anticipated brawl.

Nidhi Tripathi, National General Secretary, ABVP, said, The attack on ABVP activists studying in JNU is morally reprehensible. All students are startled by the Left's vicious attempts to terrorize everybody into submission. We earnestly request the Delhi Police and JNU Administration to take all possible measures to bring the situation on the campus under control, assuage the concerns of the traumatized students, and ensure everyone's safety. ■

‘सेवार्थ विद्यार्थी’ के माध्यम से लोगों के दर्द को बांट रहे हैं परिषद कार्यकर्ता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प ‘सेवार्थ विद्यार्थी’ के माध्यम से परिषद के कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में वंचितों के लिए आशा की किरण बन उभर रहे है। इस प्रकल्प के माध्यम से कार्यकर्ता छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग, जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तित्व विकास संगोष्ठी, पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान, सर्दियों में निर्धन बस्तियों में वस्त्र वितरण कार्यक्रम चला रही है।‘स्टूडेंट फॉर सेवा’ के डॉ. राकेश शर्मा बताते हैं कि ‘स्टूडेंट फॉर सेवा’ हिमाचल प्रदेश के द्वारा पिछले 8 महीनों में 19 कार्यक्रम किए गए। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से मंडी जेल में कैदियों के लिए मोटिवेशनल स्पीच, सुंदरनगर में विद्यार्थियों के लिए करियर कॉउंसलिंग का आयोजन किया गया। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि 4 जुलाई को पूरे प्रदेश में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया जिसमें प्रान्त के 5 स्थानों सुंदरनगर, ऊना, कुल्लू, मंडी व धर्मशाला में स्लम एरिया के बच्चों को, जो नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं, स्टडी किट प्रदान किए गए। प्रान्त के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में बुक बैंक का आयोजन किया गया जिसमें 350 जरूरतमंद विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें मुहैया करवाई गई। बालिका आश्रम सुंदरनगर में रहने वाली अनाथ व अति निर्धन बालिकाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने छोटी दीवाली मनाई। उनको नए वस्त्र उपहार के रूप में दिए, दीपमाला जलाई, मिष्ठान्न बांटे व सहभोज का आयोजन भी किया। पूरे प्रान्त के विभिन्न स्थानों पर जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, संजौली, आर.के.एम.वी. शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, सुंदरनगर, मंडी, घुमारवीं आदि स्थानों पर सुनील उपाध्याय वस्त्र बैंक के माध्यम से वस्त्र वितरण किया गया। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम निःशुल्क विज्ञान कक्षाओं को शुरू किया गया जिसमें डिग्री कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की। धर्मशाला व मंडी स्थित नेरचौक स्थित वृद्धाश्रम में सम्मानीय बुजुर्गों के साथ कार्यकर्ताओं ने समय बिताया व उन्हें फल, बिस्किट व जूस इत्यादि वितरित किये। सुंदरनगर स्थित वृद्धाश्रम में सुनील उपाध्याय जी की पुण्यतिथि 12 नवम्बर को बुजुर्गों को फल, बिस्किट नमकीन के अलावा गर्म वस्त्र उपहार स्वरूप दिए गए। ■

भारत के राष्ट्रपति से मिला अभाविप प्रतिनिधिमंडल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के समक्ष विद्यार्थी परिषद् द्वारा राष्ट्र हित में चलाए जा रहे विभिन्न गतिविधियों, संगोष्ठी, शिविर इत्यादिक क्रियाकलापों को रखा। महिला सुरक्षा हेतु परिषद द्वारा चलाए जा रहे मिशन साहसी के कार्यक्रम की उपादेयता, परिणाम से भी महामहिम को परिचित करवाया गया साथ ही शिक्षा क्षेत्र में रचनात्मक तरीके से चलाए जा रहे स्कूल बेल की भी जानकारी दी। ■

HISTORY OF VIOLENECE IN JNU

| Ramanand |

The recent horrifying incident in the JNU is a despondent story from the academic institution in India. It is not the first time that such incidents are taking place inside the university campus. In the year 2016, inside the same campus, groups of students wearing mask chanted anti-national slogan and committed sedition with the support of the Student Union of JNU. Series of violence from decades in Jadavpur University and the parts of West-Bengal and Kerala are not hidden from anyone. Similarly, the certainty and severity of the left party led vehemence and pattern of violence in West-Bengal and Kerala is seen and apparent inside the country. JNU has a history of being intolerant to another viewpoint and ideology. The question arises whether not allowing the common student to register for the upcoming session in JNU and then beating those students for not complying the boycott led by left students wing is brutal or not?

Let's See the Timeline of JNU Violence

On 4th January 2020, about 1 PM masked intruders entered inside the premises of Central Information System and committing mischiefs by damaging the Internet server. From the 3rd January continuously, students allegedly affiliated with left-wing Students Union were present on the spot and near the server room and not allowing college administration to operate Central Information System.

Also, the same day on 4th January heated exchange of words took place between common students who were manhandled by Left student for not complying their directions and boycott.

This should be also noted that previous month left students boycotted examination in the institution and also threatened to those supporting.

History of Violence in JNU

In the year 2016, incident that shook national media and public at large was the episode at Jawahar Lal Nehru University when left groups supporting the programme against the death sentence and hanging of Afzal Guru, who was convict of Parliament Attack,2001 and Kashmiri separatist leader Maqbool Bhat. The organizers of the event were former members of the Democratic Students Union (DSU) and with the support of the left student's organization, they were hosting this event. University administration denied the permission for such an event inside the JNU premises by withdrawing the permission for the event shortly before the event because there were protests against such event by ABVP and other student groups. The event also led to conflict and clashes between various student groups on the campus. A video that went viral by national media channels testified the fact that unknown groups of students who were wearing a mask came inside the university and shouted anti-India slogans. This current event is not different from the series of events that happened in 2016 and if you will study the pattern you can decode the design of violence in JNU.

In the year 1983, in the series of chain reaction where On April 27, Jalees Ahmed, a student of Jhelum Hostel was transferred to Ganga Hostel on disciplinary grounds. Which led to violence and the confrontation over what was an insignificant administrative issue which was provoked by the students. This incident led to lengthy gherao where more than 100 students entered into vice-chancellor's residence and created serious

law and order in the problem. Students association carried massive violence in the year 1983 against the order of vice-chancellor and teachers. This student's violence was criticised in all corners of the country. As a consequence, to restore status quo inside the campus and to function the university in a normal way, CRPF and police were asked to enter inside the premises and to deal with rioters and section 144 were imposed along with several provisions of Indian Penal Code were applied against groups of violent protestors in JNU.

Sad to see the Institute of eminence is turning into a place for violence. JNU has its reputations and credibility in the academic domain of India and abroad. However, such incidents are horrifying in the university campus and question the credibility of the institutions that were built over a period of time. This should not be the level of the student union to harass general and common students those who are interested in studies.

As a concerned citizenry, we should request people not to make/form your opinion based on some random videos or fake screenshots. You should see the whole incident in totality and a series of events happening in JNU campus from the last couple of days. Left supported students and JNU student union were not allowing the students to study, continuously trying to create a nuisance, mischief and ferocious activities inside the campus. The violent form of protests by left-leaning students' groups and SFI in these institutions are repeatedly done over the period of time. This is what the history and timeline of events tell about the left led violence in JNU. However, this type of violence is shocking and condemnable. JNU should not become the laboratory of the political experiment of the political parties.

We need to also make accountable to those who fueling the violence and getting mileage from this violence. It has been evident that from CAA movement, media has become a party, their role as an observer has been blurred. They are reporting on JNU issue according to their ideological and political position. Now, they are not reporting only facts, they have started to making facts as per their convenience.

The Bollywood celebrities who are not getting enough coverage or media attention in odd days, have joined the misguided movement on CAA-NRC to get some media attention and public buzz. On JNU issue also, the same last media celebrities making comments without checking basic facts. The campus has become a place where they want to premiere their movies because it is more cost-effective than the hotels or multiplexes.

We need to understand that their interest does not lie in student's problem but they want to make their career out of it. As a student, we need to aware that who are coming in our campuses and what are their purpose? ■

घुसपैठियों व शरणार्थियों में फर्क करना जरूरी

| सुनील आंबेकर |

भारत का विभाजन 1947 में हुआ और वह भी धर्म के नाम पर। मुस्लिम पूजा पद्धति करने वालों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना। भारत ने यहां बसे सभी मुस्लिमों को भी समान नागरिक के रूप में भारत में शामिल करने की घोषणा की और आज तक उसका पालन हो रहा है और बाद में भी होता रहेगा। परंतु पाकिस्तान (पूर्व व पश्चिम) और बाद में बांग्लादेश ने इसका कभी पालन नहीं किया। इसके विपरीत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध तथा ईसाई एवं सभी गैर मुस्लिम मतवलंबियों पर अत्याचार किए गए। परिणामस्वरूप वर्ष दर वर्ष इनकी जनसंख्या घटती चली गई। कई लोग दयनीय परिस्थितियों में 1947 से सतत पलायन करते रहे। परंतु 70 वर्षों तक उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई, क्योंकि भारत में तथाकथित सेक्युलर(धर्मनिरपेक्षता) के नाम पर अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हिंदुओं की उपेक्षा का पर्याय बनती चली गई। विस्तारवाद के षड्यंत्र के तहत लाखों की संख्या में मुस्लिम घुसपैठियों का बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवेश चलता रहा। कई सेक्यूलर दल इन्हें अपना पक्का मतदाता बनाकर सत्ता में पहुंचने की राजनीति में जुट गए। असम में तो नॉनअसामिस(गैर असमी लोगों की पार्टी) एआईयूडीएफ (ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) जैसे राजनीतिक दल का निर्माण हुआ, जिसने अनेक विधानसभा क्षेत्रों में अपना निर्णायक दबदबा बना लिया। यह असम का हर व्यक्ति जानता है कि शरणार्थी हिंदू इस तरह से कभी भी असम की पहचान एवं राजनीति में खतरा नहीं बने। इसके विपरीत जिन विधानसभा क्षेत्र में नॉन असामीज एआईयूडीएफ जैसे दल के प्रभाव से बचने में शरणार्थी हिंदुओं की मदद ही हुई है।

असम की परंपराएं एवं भाषा केवल असम की नहीं अपितु भारत की परंपरा पहचान एवं संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। असमी भाषा, गमछा, शंकरदेव, बीहू और पीठा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है तथा इसकी रक्षा भारतीय संस्कृति की रक्षा है।

असम की धरती पर शंकरदेव के जन्म स्थान और माजुली जैसे क्षेत्र असम की पहचान के मुख्य केंद्रबिंदु बने हैं, पर घुसपैठियों ने कैसे कब्जा बनाया है इसे असम का हर व्यक्ति जानता है। अभी तक तथाकथित सेक्युलर राजनीति के चलते आसू (AASU) ने भी कभी इस पर मोर्चा नहीं खोला है। कई संगठनों ने असम के लोगों के घुसपैठ विरोधी आंदोलन को हमेशा अपने हित में शरणार्थी विरोधी आंदोलन बनाकर असम के हितों की उपेक्षा की है। उल्फा जैसे संगठन तो असम के हित का चेहरा लेकर बांग्लादेश में अपना केंद्र बनाकर घुसपैठियों की वकालत करते हुए भटक गए। असम के लोगों ने बड़ी आशा के साथ असम गण परिषद को सत्ता पर बिठाया परंतु वह बुरी तरह निराशा लेकर आए। कांग्रेस ने तो अपनी तात्कालिक स्वार्थों की राजनीति के चलते हमेशा सेक्युलर के नाम पर अल्पसंख्यक तुष्टि की तथा हिंदू हित की उपेक्षा की, अर्थात असमी पहचान की उपेक्षा की। इतने वर्षों में कांग्रेस ने असम में घुसपैठियों को रोकने की कोई उचित कार्रवाई नहीं की। शरणार्थियों की कोई उचित व्यवस्था पिछले 70 वर्षों में नहीं की। यही कारण है कि आज असम में इतनी बड़ी संख्या में एक तरफ बांग्लादेश घुसपैठियों ने 'असमी पहचान' पर संकट खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में वर्षों से बसे शरणार्थियों की जिम्मेदारी असम पर आई है। इन समस्याओं पर अब समाधान का रास्ता उत्तेजना में या भावनाओं में नहीं, अपितु शांतिपूर्वक विचार विमर्श से निकलेगा।

असम की परंपराएं एवं भाषा केवल असम की नहीं भारत की परंपरा पहचान एवं संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। असमी भाषा, गमछा, शंकरदेव, बीहू और पीठा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है तथा इसकी रक्षा भारतीय

संस्कृति की रक्षा है। इस समय यह समझना जरूरी है कि भारत की इस विविधता से परिपूर्ण संस्कृति के हितों की रक्षा कैसे होगी। स्वार्थी राजनीति के झूठे सेकुलरवाद में हम गलत दिशा न पकडें, यह ध्यान रखना जरूरी है। इस बीच शरणार्थियों के रक्षा की जिम्मेदारी बढ़ी है। इन विषयों पर विद्यार्थी परिषद प्रारंभ से असम आंदोलन के समय से सक्रिय है। इसी संदर्भ में 2 अक्टूबर 1983 को विद्यार्थी परिषद ने 'असम आंदोलन' के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर गुवाहाटी में प्रदर्शन किया था तथा देशभर में व्यापक जनजागरण के जरिये यह विमर्श खड़ा किया था कि यह समस्या केवल असम की नहीं बल्कि समूचे देश की है। 1947 में विभाजन के समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शक्ति के अनुसार असम के सभी क्षेत्र में शरणार्थियों के लिए सेवा शिविर लगाए थे तभी से असम को 1996 से चल रहे बंगाल विभाजन के षड्यंत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया है।

दरअसल वर्ष 1947 में विभाजन के समय भी जिन्ना सहित कई नेताओं की नजर असम पर थी। घुसपैठियों को घुसा कर उसे पूरा करने के प्रयास निरंतर चलते रहे। आज जब वर्तमान सरकार असम सहित पूरे देश में फैले शरणार्थियों को नागरिकता देकर कर्तव्य पूर्ति कर रही है तथा एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन) को लागू करते हुए घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई की योजना बना रही है तब, इस विरोध के कारणों को समझना जरूरी है। तथाकथित सेक्यूलरवार की आड़ में कुछ लोग घुसपैठियों और शरणार्थियों को असम के पहचान के संकट के रूप में प्रस्तुत कर देशभर में विरोध के स्वर उठा रहे हैं। इस मायाजाल की राजनीति से बाहर निकल कर जल्द ही असम सहित पूरे देशवासियों को इसमें फर्क समझना जरूरी है अन्यथा हम एक भयंकर संकट में फंस जाएंगे जिसके परिणाम पूरे देश को, विशेषकर असम को भुगतना होगा। इन दोनों में फर्क ना करने से हम आखिरकार घुसपैठियों का संरक्षण करेंगे तथा विभाजनकारी एवं कट्टरपंथी अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम विस्तारवाद को आमंत्रण देंगे। भारत के मुस्लिम भारत के हैं, उन्होंने भारत में रहने का फैसला 1947 के समय ही लिया था तथा निसंदेह उन्हें इसके लिए किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है तथा कोई भी नया कानून या विविध प्रक्रिया उन्हें इससे वंचित नहीं कर सकती। यह भारत की कल्पना तथा परंपरा के अनुसार ही है।

प्रताड़ित शरणार्थियों को मिलेगा पूरा सम्मान
घुसपैठियों का नहीं होगा कोई स्थान
यह नया हिंदुस्थान है यह नया भारत है। ■

(लेखक अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री है एवं द आरएसएस रोडमैप्स फॉर 21 सेंचूरी पुस्तक के लेखक भी हैं।

परमश्रद्धेय स्वामी पेजावर श्री स्वामी विश्वेश तीर्थ जी को विनम्र श्रद्धांजलिः अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, परमश्रद्धेय स्वामी पेजावर श्री स्वामी विश्वेश तीर्थ जी के इस नश्वर जगत को त्यागने पर गहरा शोक व्यक्त करती है। स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज का राष्ट्र और धर्म के संबंध में किया गया चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण तथा देश की भावी पीढ़ियों को सही दिशा दिखाने में सहायक है।

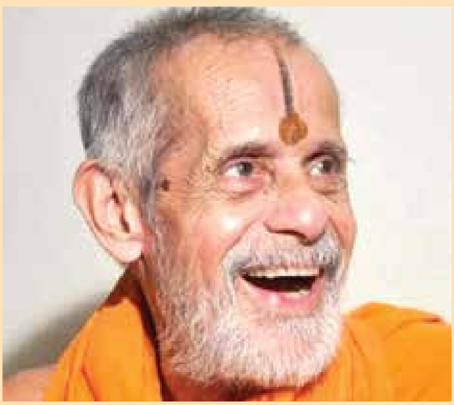

श्री स्वामी विश्वेश तीर्थ जी के वैकुंठलीन होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एस सुब्बैया, महामंत्री निधि त्रिपाठी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, पूर्व राष्ट्रीय संगठनमंत्री सुनील आम्बेकर एवं पूर्व राष्ट्रीय सह संगठनमंत्री के.एन. रघुनन्दन जी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ■

नागरिकता कानून: कैंपस विद्रोह शहरी नक्सलवाद नहीं तो और क्या है?

।श्रीनिवास।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैल जाना, इस बात की ताकीद करता है कि राष्ट्र विरोधी शक्तिया देश को कैसे अशांत करने पर तुली हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हसनपुर पुलिस चौकी में आग लगा दी गयी। उस भीड़ में जितनी संख्या थी उसमें अधिकतर स्कूली बच्चे नजर आ रहे थे। इतने कम उम्र के बच्चों के द्वारा हिंसा में शामिल इस बात की पहचान है कि उनके दिमाग में जहर उड़ेला जा रहा है। चंद लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनकी मासूमियत का गलत प्रयोग कर रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि स्थिति जब अराजकता की हो तो विदेशी शक्तियाँ भी आग में घी डालने का कम करती है, बड़े पैमाने पर फंडिंग भी विदेशों से होती है। राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकते है. यह विषय अत्यंत ही दुखद और चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इससे किसी भी मुस्लिम परिवार को डरने कि जरुरत नहीं है। किसी भी तरीके से यह कानून उनके विरोध में नहीं है। यही बात गृह मंत्री ने भी दुहरायी, उसके बाद भी हिंसा की घटनायें होती रहीं। वह भी चुनिंदा जगहों पर। मुस्लिम बहुल इलाके और कैंपस इसके मुख्य केंद्र बने। जामिया में जमकर बवाल हुआ। फुटेज में पाया गया कि कैंपस के भीतर असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर पत्थर फेंके गए और सरकारी सम्पति को तहस - नहस किया गया। कुछ दलों के चयनित विधायकों ने भी हिंसा को बढ़ाने की पहल की है। समाचार पत्रों में दर्जनों ऐसे आलेख लिखे गए जो विद्रोह का खुल्लमखुल्ला आगाज कर रहे हैं। अरुंधती रे, प्रोफ. आशुतोष वार्ष्णेय और तमाम अपने आप को लिबरल विचार के ठीकेदारों ने देश के विरोध में आंदोलन करने की आम जनता से अपील की है। अलीगढ और जामिया में छात्रों ने जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया है और सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाया है, वह एक घोर अपराध है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विपक्ष की अपील को खारिज करते हुए हिंसा की कड़े शब्दों में आलोचना की है। यहाँ तक कि जामा मस्जिद के इमाम ने भी मुस्लिम समुदाय को कहा है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है इसलिए ऐसे लोगों की भड़काऊ बातो में नहीं आए। इसके बावजूद इस कानून को राजनीतिक रंग देने की कोशिश जारी है। क्या ऐसा करना उचित है? देश के मुसलमानो को गलत तथ्यों के द्वारा गुमराह करना एक जुर्म नहीं है? भीड़ के द्वारा राष्ट्रीय सम्पति का नुकसान एक संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता? ये तमाम मसलों पर आम जनता को सोचना होगा कि कौन सी शक्तियां देश को अस्थिर करना चाहती है? उनका मकसद क्या है?

इस कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर के लोगों को भी बरगलाया गया। राजीव गाँधी के द्वारा असम गण परिषद् के साथ जो असम समझौता हुआ था,उसमें मुद्दे क्या थे? जब वही बात इस सरकार ने सबके हितों को ध्यान में रख कर एन.आर.सी को लागू किया तो उस पर बवाल मचा। उसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक को रोकने की कोशिश की गयी। जब यह कानून बन गया तो उसके माध्यम से धार्मिक विद्वेष फैला कर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यहाँ पर इस बात को समझना जरुरी है कि भारत के पड़ोसी देशो में अल्पसंख्यकों के साथ 70 में घोर अत्याचार होता रहा है। देश के बंटवारे के समय पूर्वी बंगाल जो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ पर हिन्दुओ का प्रतिशत 35 था जो 1971 में घटकर 21 प्रतिशत हो गया और आज तक़रीबन 7 प्रतिशत शेष है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसमें से अधिकतर हिन्दू परिवार अत्याचार से तंग होकर वर्षों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आजीविका चला रहे है। नए

सिरे से उनको बाहर से बुलाकर बैठाने की बात नहीं है। अगर है भी तो यह जानना जरुरी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान तीनों ही इस्लामिक देश है। नागरिकता के प्रश्न पर सभी धर्मों को एक भाव में नहीं देखा जाता। धर्म परिवर्तन की कोशिश बल और धन के बूते पर किया जाता है। भारत में बंटवारे के बाद से लेकर आज तक ऐसी बातें नहीं हुई हैं और न ही संभव है। इसलिए तथाकथित बुद्धिजीवी और नेताओं के द्वारा यह अफवाह फैलाना कि मुस्लिम समुदाय को यह सरकार हाशिये पर धकेलना चाहती है, उनको दोयम दर्जे की नागरिकता देने का षड्यंत्र रच रही है, क्या ऐसा करना देश द्रोह नहीं है?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद आंदोलन की अगुआई की है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें मिलीं है। इससे असामाजिक तत्व को बल मिला और वे देश की व्यवस्था को चुनौती देने लगे। यही हालत दिल्ली के जामिया में हुआ। मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाको में सामाजिक सौहार्द तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अजीब संयोग और दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने मुस्लिम समुदाय की बुनियादी कमियों और दुर्गुणों को दूर कर उनको मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है तो तमाम राजनीतिक पार्टिया जो उनके कुनबे के बल पर सत्ता में आना चाहती है, सामाजिक ताने बाने को तोड़कर देश को राजनीतिक रूप से अस्थिर करना चाहती है। लेकिन उनका मंसूबा सफल नहीं होगा। क्योंकि देश उनकी दोहरी राजनीति और मौकापरस्ती को समझ चुकी है। देश सच और अफवाह को भी जानती है। यह केवल राष्ट्रविरोधी शक्तियों का जमघट है जिनकी तादाद बहुत अधिक नहीं है।

यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट दिखायी दे रही है कि कैसे कैंपस की राजनीति में जहर घोला जा रहा है ? विद्यार्थी देश का भावी कर्णधार है। पहले जेएनयू में फीस को लेकर कैंपस से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया, फिर नागरिकता कानून को लेकर जामिया और अलीगढ में बवाल मचाने की कोशिश की जा रही है, फिर इनको एक सूत्र में पिरोकर देश व्यापि आंदोलन देने की साजिश रची जा रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी जैसे कई पार्टिया है जिनकी दुकानें मुस्लिम राजनीति की वोट बैंक पर चलती थी.

इस तरह की अव्यवस्था फैलाकर देशव्यापी अराजकता की स्थिति को पैदा करने वाले और कोई नहीं बल्कि शहरी नक्सली ही है। कभी मॉब लिंचिंग को लेकर तो कभी कैंपस में फी वृद्धि को लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। इस कुत्सित मानसिकता के पीछे वही

शक्तियाँ है जो देश को अस्थिर करना चाहती है। शहरी नक्सली जिसका मकसद कैंपस के छात्रों को उत्तेजित कर देश को विकास के रास्ते से नीचे धकेलना है। भारत विरोधी शक्तियों की एक मजबूत शृंखला है। कैंपस से लेकर संसद तक इनके तार जुड़े हुए हैं। उदारवादी विचारधारा के नाम पर देश की राजनीतिक ढांचे को तोड़ना इनकी आदत है। जिस तरीके से एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक पर कुछ दलों ने विरोध की राजनीति की और धर्म को अपना आधार बनाया वह अपने आप में उस भारत विरोध की तस्वीर पेश करता है। ये राजनीतिक शक्तियाँ अपने आप को लिबरल थॉट की मानती है। यानि उदारवादी सोच देश को तोड़ने और कमजोर करने के लिया बनाया गया है। संसद में राजनीतिक पार्टियाँ और कैंपस में उनके बुद्धिजीवी मसीहा जो विद्वता का अलख दुनिया में जलाना जानते है लेकिन देश को अँधेरे में रखना पसंद करते है। जिनकी सोच कश्मीर को पाकिस्तान सौपने की है और राष्ट्र के सपने को खंडित करने की है।

शहरी नक्सलवाद पैदा कैसे होते हैं? इस बात को समझना अब आम जनता के लिए मुश्किल नहीं है। देश में छात्रों की आड़ में राजनीति को मानवीय शक्ल देने का ढोंग उदारवादी बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाता है। उनकी निगाह में राष्ट्र एक बेमतलब की चीज है।

शहरी नक्सलवाद पैदा कैसे होते हैं? इस बात को समझना अब आम जनता के लिए मुश्किल नहीं है। देश में छात्रों की आड़ में राजनीति को मानवीय शक्ल देने का ढोंग उदारवादी बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाता है। उनकी निगाह में राष्ट्र एक बेमतलब की चीज है। देश के राष्ट्रीय खजाने से विदेशो में मौज करने वाली यह जमात विदेशो में अपने ही देश को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचते हैं और विदेशो में अपनी शान बटोरते है, देश ऐसे लोगो को पहचान चुका है।

लिबरल थॉट के बुद्धिजीवि जिनकी तादाद बहुत नहीं है लेकिन उनका विस्तार जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में जरूर है। इनकी ठेकेदारी अन्य संस्थाओ में भी चलती है। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो अपने देश को ही कमजोर करने की साजिश रचते हैं। निश्चित रूप से उसका केंद्र जेएनयू है। भारतीय रकम पर विदेशों में जाकर अपने ही देश की आलोचना को अपनी बौद्धिक संपदा मानते थे। प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय ने गुजरात दंगों के बाद वाशिंगटन डीसी में 10 जून 2002 को वहां की सरकारी समिति 'यूनाइटेड स्टेटस कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम' के सामने भारत सरकार के खिलाफ गवाही दी। इस कमीशन की सुनवाई का उद्देश्य अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा हुआ था। किसी तरह के कई बुद्धिजीवियों का अड्डा विदेशों के विश्वविद्यालयों में सक्रिय हैं जो भारत विरोधी मुहिम में शामिल हैं। उसमें से एक हावर्ड विश्वविद्यालय का एक खेमा है जो स्टीम फॉर्मर के द्वारा चलाया जाता है। इसका नाम 'इंडो-यूएस रिसर्च' है। इनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम करना है। प्रोफेसर रोमिला थापर इस ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं।आज देश दुनिया के सामने एक नयी पहचान के साथ खड़ा है। राष्ट्र अपनी विस्मृत सांस्कृतिक धरोहर को बटोरकर दुनिया को एक नयी दिशा देने की क्षमता रखता है। 2014 के बाद कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से एक अलग भारत की दासतां शुरू होती है। भारत का उभरना कई लोगो को रास नहीं आ रहा है। इसलिए विद्रोह का सामियाना खड़ा किया जा रहा है। देश के लिए यह चिंता का विषय है।

नागरिकता कानून किसी भी तरह से धर्म प्रेरित नहीं है और न ही किसी भी धार्मिक समुदाय के विरोध में है। इसलिए धर्म के नाम पर मचाया जा रहा बवाल भी राष्ट्र विरोध की श्रेणी में आता है। चूंकि देश की वर्तमान व्यवस्था अपने सच और राष्ट्र हित के लिए कटिबद्ध है। उसका मकसद न केवल देश की प्रगति करना बल्कि ऐसे तत्वों की पहचान करना जो राष्ट्रव्यापी दंगा और लूट-पाट को अपना राजनीतिक विरोध मानते हैं। विरोध की भी एक मर्यादा है, अगर वह मर्यादा की सीमा टूटती है तो सरकार को उन्हें दण्डित करने के साधन भी सुनिश्चित करने होंगे। आम जनता को देश हित की बातो को समझते हुए ऐसे गुमराह लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में सरकार की मदद करनी होगी। नागरिक समुदाय भी अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकता। ■

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री हैं।)

'Death Warrant' for the murderers and rapists is real tribute to Nirbhaya: ABVP

Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad heartily welcomes the Patiala House Court's decision to issue 'death warrant' to the rapists and murderers of Nirbhaya. This decision would act as a strong deterrent against such heinous crimes in future.

ABVP initiated a nation-wide movement to bring the rapists and murderers of Nirbhaya to justice. ABVP also demanded that stringent laws be put in place to deter such crimes in future. ABVP sustained its agitation till the Juvenile Justice Bill was successfully enacted in 2016.

Vinita, National Secretary, ABVP, said, We have been consistently and relentlessly demanding the establishment of fast-track courts for the expeditious trial of the accused. The Nirbhaya verdict is a watershed moment, and inspires optimism regarding the eventual mitigation and subsequent elimination of crimes against women, thereby giving testament to the constitutionally enshrined values of liberty and equality. ■

THE ATTACK BY THE SECTARIAN FUNDAMENTALIST ON NANKANA SAHIB IN PAKISTAN IS UNFORUTUNATE : ABVP

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad strongly condemns the attack on the gurudwara at Nankana Sahib in Pakistan by the sectarian fundamentalist. The incidents of similar atrocities on religious minorities in Pakistan on humanity. When the religious minorities are facing attacks, the silence of the alleged Human Rights Activists and global leader is disappoints and it even puts a question mark on them for calling themselves human rights protectors.

ABVP's National General Secretary Nidhi Tripathi Said The way minorities are being attacked in India's neighbouring countries are extremely worrying for the whole world. It is Very Unfortunate that in an Islamic country like Pakistan, State sponsored persecution of religious minorities in being done systematically. The global leaders must come to forward to prevent this unfortunate situation and everyone must stand to protect human right by becoming the voice of minorities together. ■

अहमदाबादः अभाविप कार्यालय पर एनएसयूआई का हमला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) गुजरात प्रांत के अहमदाबाद कार्यालय पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, जिसमें अभाविप के कई कार्यकर्ताओं चोटिल हो गये। अभाविप ने यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला कर कार्यालय भी तोड़ा गया है। अभाविप ने इस बाबत पुलिस से शिकायत भी की है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही अभाविप के नासिक तथा पुणे कार्यालय पर भी हमला किया गया था। अभाविप ने बताया है कि कुछ दिन पहले एनसीपी ने अभाविप के नासिक तथा पुणे कार्यालय पर हमला कर कार्यालय में तोड़फोड़ की है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है तथा अलोकतांत्रिक है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं की कड़ी निंदा करती है तथा इस प्रकार के राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जा रहे विष-वमन को तत्काल रोकने की मांग करती है। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हैं, हमारा स्पष्ट मत है कि मतभेदों पर संवाद होना चाहिए। ■

जेएनयू हिंसा की पटकथा 28 अक्टूबर को ही लिख दी गई थी : अभाविप

जेएनयू हिंसा पर अभाविप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जेएनयू के शिक्षक हमें धमकाते हैं। परिषद के मुताबिक जो व्हाट्सएप ग्रुप और चैट वायरल किया रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। उस ग्रुप के सभी नंबरों की जांच हो ताकि उसकी सच्चाई का पता लगाया जा सके।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि जेएनयू हिंसा पर चर्चा हो रही है लेकिन उसे सिर्फ 5 जनवरी तक ही सीमित कर दिया गया। लेकिन यह देखना होगा कि हिंसा सिर्फ 5 जनवरी को ही नहीं हुई। यह देखना होगा कि 28 अक्टूर 2019 से लेकर 5 जनवरी 2020 तक कैंपस में क्या विवाद हुआ।

निधि त्रिपाठी ने कहा कि इस आंदोलन को फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन कहना गलत होगा। यह जेएनयू पर नक्सली हमला था। इसकी पटकथा 28 अक्टूबर 2019 को लिखी गई थी जो 5 जनवरी 2020 को हिंसा के रूप में सामने आई जब खून बहा और मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि वामपंथी छात्र संगठन जेएनयू के वामपंथी शिक्षकों के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। वे सभी अध्यापक राजनीति से प्रेरित हैं और

वे छात्रों को अपनी भयानक राजनीति खेलने के लिए उपयोग कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से विनाशकारी है और इसका उद्देश्य समाज में अस्थिरता का माहौल लाना है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि " जो छात्र-प्राध्यापक अकादमिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं , उनको लेफ्ट के लोगों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है एवं कंगारू कोर्ट के माध्यम से उनके सामाजिक बहिष्कार का निर्णय सुना दिया जा रहा है । इस तरह वैचारिक अस्पृश्यता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है । ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों की वजह से कैंपस का माहौल खराब हो गया है । " ■

गोरखपुरः अभाविप द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,गौरक्ष प्रांत द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें हाईस्कूल के 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, इंटरमीडिएट के 70% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, स्नातक व परास्नातक के 60% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं NCC, NSS SPORT के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाओ को सम्मानित किया गया। विशेष रूप से दिव्यांग प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ लगभग 39 शिक्षण संस्थानों के 1500 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि युवाओं को विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हुए उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन्ही के आदर्शों पर चलते हुए आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उन्होंने स्वामी जी के सभी जीवन वृत के माध्यम से युवा को राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रेरित किया। तथा अपने जीवन के प्रतिकूल समय का उदाहरण देते हुए जीवन में सीख लेने की बात की। अपने वक्तव्य में फ़िल्म सुपर 30 का भी जिक्र किया एवं स्वामी जी के संदेश और डॉ० कलाम साहब के व्यक्तित्व से सीखने की सलाह दी। उन्होंने ने सफलता के चार सूत्र बताये, 1-असीम धैर्य 2- गहन अध्ययन 3- दृढ़ इच्छा 4- अथक परिश्रम के साथ आप कोई भी कार्य कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के अपने स्मृति को भी साझा किया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अभाविप के अखिल भारतीय राज्य विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख श्रीहरि बोरिकर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मात्र शैक्षणिक समस्याओं को लेकर ही नहीं कार्य करता अपितु छात्र-छात्राओं के बौद्धिक, शारीरिक व आर्थिक विकास हेतु अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करती है जिससे कि विद्यार्थी भविष्य में एक सामाजिक, राष्ट्रवादी नागरिक बने। उन्होंने कहा कि हम सब के अंदर मै रहू या ना रहूं का भारत ये रहना चाहिए का भाव रहना चाहिये। वहीं अभाविप की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो० उमा श्रीवास्तव ने कहा कि परिषद द्वारा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है, जिनमें से एक प्रतिभा सम्मान समारोह है। विद्यार्थी परिषद देशभर में छात्र- छात्राओं के गुणोत्तर विकास हेतु शिक्षा क्षेत्र के समस्याओं को लेकर लड़ने वाले एक अग्रणी छात्र संगठन के रूप में देश भर में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐसे लोग शैक्षणिक परिसरों में विद्यमान है जो देश के टुकड़े करने का सपना देखते हैं किंतु ऐसे शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थी परिषद की उपस्थिति उनको हतोत्साहित करने का काम करती है, ऐसी विध्वंसक शक्तियों को समाप्त करने का काम करती है। इस अवसर पर प्रान्त अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही जी ने सभी अतिथियों व छात्र-छात्राओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 'देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें' इस भाव के साथ विद्यार्थी परिषद छात्र-छात्राओं के बीच में कार्य करती है। आभार ज्ञापन महानगर उपाध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश राय ने किया। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' जनवरी 2020 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in

rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

भारतीय कला व संस्कृति के उत्थान के लिए विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण : निधि त्रिपाठी

भारतीय कला व संस्कृति के उत्थान के लिए विद्यार्थियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर के निलाद्री बिहार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राष्ट्रीय कला मंच द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिभा संगम कार्यक्रम के उदघाटन सत्र में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने यह बात कही। उन्होंन कहा कि विभिन्न परिसरों में से कलाकार छात्र- छात्राओं को मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कला मंच हर दो साल में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस प्रतिभा संगम कार्यक्रम में राज्य व देश के विभिन्न कैंपसों से एक हजार से अधिक छात्र- छात्राएं भाग ले रही हैं। भारतीय कला जैसे नृत्य, संगीत, अभिनय, चित्रकला, स्वरचित कविता गायन, रंगोली आदि में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए अपना प्रतिभा प्रदर्शन करने का यह एक बडा माध्यम है। प्रतिभा संगम कार्यक्रम केवल विद्यार्थियों में प्रतियोगिता ही आयोजित नहीं करता बल्कि उन्हें वरिष्ठ व नामचीन कलाकारों के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

उदघाटन कार्यक्रम में पद्मविभूषण तथा राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा ने कहा कि भारत की महान संस्कृति को आगे बढाने की दिशा में विद्यार्थियों को आगे आना चाहिए।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय़ कला मंच के संयोजक तन्मय दास ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से अवगत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में राष्ट्रीय अभिनय विद्यालय वाराणसी के अध्यक्ष रामजी बाली,. पूर्व सांसद तथा अभिनेता सिद्धांत महापात्र, ओडिशा चलचित्र निगम के अध्यक्ष सत्यव्रत त्रिपाठी, अभिनेत्री अनु चौधरी, अभिनेता बाबु शान महांति, व्यंग कवि ज्ञान होता उपस्थित थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष अजीत दास ने स्वागत भाषण दिया।

भारतीय कला- संस्कृति विविधता में एकता का संदेश देता है : प्रताप षडंगी

भारतीय कला- व संस्कृति विविधता में एकता का संदेश देता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व दरबार में पहुंचायें। राष्ट्रीय कला मंच द्वारा भुवनेश्वर के निलाद्री बिहार शिशु मंदिर में आयोजित प्रतिभा संगम कार्यक्रम के दूसरे दिन केन्द्रीय मंत्री प्रताप षडंगी ने अपने उदबोधन में यह बात कही। श्री षडंगी ने संस्कृत में अपना अभिभाषण रखा। प्रतिभा संगम के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें नृत्य, संगीत, स्वरचित कविता पाठ आदि प्रतियोगिता आयोजित किये गये। इन प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को नामचीन लोगों ने प्रशिक्षण भी दिया। संगीत प्रतियोगिता के जज के रुप में ओडिया संगीत निदेशक मन्मथ नाथ मिश्र, प्रेम आनंद, गुडली रथ, शैलभामा शामिल थे। इन लोगों ने प्रतियोगियों के गायन व संगीत के गुर भी सिखाया। इसी तरह कविता आवृत्ति में कवि डा शुभकुमार दास, अमीय महापात्र व व्यंग कवि ज्ञान होता जज के रुप में उपस्थित होकर कविता पाठ में शामिल छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। नृत्य प्रतियोगिता में जज के रुप में विशिष्ट नृत्य निदेशक मृत्युंजय पंडा, अंतरराष्ट्रीय नृत्य शिल्पी डा श्रीनिवाक घटुआरी एवं जया विश्वास उपस्थित थे। इन लोगों ने इस प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण व उनके नृत्य में कैसे अधिक सुधार लाया जा सकता है इस पर भी चर्चा की।

राष्ट्रीय कलामंच द्वारा आयोजित सांस्कृतिक प्रतिभा संगम के हुआ समारोप को संबोधित करते हुए श्री जगन्नाथ मिश्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. हरिहर होता ने कहा कि भारतीय कला व संस्कृति की पूरे विश्व में विशेष पहचान है। भारत की संस्कृति व कला को आगे बढाने व वैश्विक स्तर पर आगे रखने के लिए विद्यार्थियों को प्रयास करने पडेंगे। इस इस कार्यक्रम के अंतिम दिन भी पूरे राज्य से व राज्य के बाहर से आये हुए छात्र – छात्राएं नृत्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय, स्वरचित कविता, रंगोली आदि प्रतियोगिता में भाग लिया। अभिनय प्रतियोगिता में विशिष्ट ओडिया फिल्म निदेशक अशोक पति, फिल्म अभिनेता जीवन पंडा व प्रीतिराज सतपथी जज के रुप में शामिल थे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में ओडिया फिल्म जगत के संगीत निदेशक मन्मथ नाथ मिश्र, व्यंग कवि ज्ञान होता, समरेश राउतराय व अन्य भी उपस्थित थे। अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र- छात्राओं को सम्मानित किया गया। ■

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा **दिल्ली** विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नेतृत्व में छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली,जिसमें बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हुए। रैली नार्थ कैंपस के आर्टस फैकल्टी से शुरू होकर छात्रा मार्ग होते हुए केन्द्रीय पुस्तकालय(सेन्ट्रल लाइब्रेरी) के सामने विवेकानंद प्रतिमा पर जाकर खत्म हुई। इस रैली में शामिल छात्रों ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देशहित में है, इसमें नागरिकता देने की बात की गयी है न कि नागरिकता छिनने की बात, इसलिए जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें किसी से भयभीत होने आवश्यकता नहीं है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़कर माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों के कैंपसों को अराजकता का अड्डा बनाने की कोशिश है लेकिन देश के छात्र इसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। शरणार्थियों ने जो अत्याचार सहे हैं, उस दर्द को समझने की जरूरत है, यह एक्ट शरणार्थियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। वहीं अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि बीते दिनों डीयू में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में खड़े लोगों द्वारा छात्रों को परीक्षा देने से रोका जा रहा था, जिससे छात्र भयभीत महसूस कर रहे थे जिसके बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद छात्रों को परीक्षा देने दिया गया। इस तरह की गुंडागर्दी को छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पंजाब विश्वविद्यालय **चंडीगढ़** में अभाविप कार्यकर्ताओं ने सीएए के पक्ष में समर्थन मार्च निकाला,

ने कहा कि देश में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वहीं बुंदी (राजस्थान) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीएए के समर्थन में कॉलेज के गेट से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। जिला संयोजक पंकज गुर्जर ने सभी छात्र-छात्राओं को नागरिक संशोधन अधिनियम के बारे जानकारी दी और इस अधिनियम से भारत में रह रहे किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी।

नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थन में उस्मानिया विश्वविद्यालय, **हैदराबाद** के एनसीसी गेट पर आर्ट्स कॉलेज से अभाविप कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। परिषद ने छात्रों को सीएए के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें किसी समुदाय के लोगों को बाहर करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। यह एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। अभाविप के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य एम. राघवेंद्र ने कहा कि हमें केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए। इस एक्ट पर फैलाई गई भ्रांतियों को दूर करने के लिए परिषद कॉलेज के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे, चूंकि हमें पता है कि वास्तव में अधिनियम में क्या है। उन्होंने दावा किया, देश भर में हो रहे सभी विरोध विपक्षी दलों द्वारा समर्थित हैं। वहीं प्रवीण रेड्डी ने कहा कि सीएए देश के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के मन में गलतफहमी भर कर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

जो गर्ल्स हॉस्टल -4 से शुरू होकर स्टूडेंट सेंटर पर जाकर खत्म हुआ। इस मौके पर परिषद कार्यकर्ता पूरे रास्ते वी वेलकम सिटीजनशिप बिल और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई.. हम सब भाई भाई, तुम धर्मवाद से तोड़ोगे- हम राष्ट्रवाद से जोडेंग़े इत्यादि के नारे लगाते हुए स्टूडेंट सेंटर पहुंचे।

विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मार्च करते हुए स्टूडेंट सेंटर पहुंचे तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने परिषद की रैली को बाधित किया और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची और एनएसयूआई के पांच कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और सेक्टर 11 के थाने में ले गई।

वहीं अभाविप कार्यकर्ताओं ने सीएए-एनआरसी के समर्थन में **हल्द्वानी** (उत्तरांखंड) में तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता की जय और वंदेमातरम की नारेबाजी करते हुए युवाओं ने एमबी इंटर कॉलेज मैदान से नैनीताल रोड होते हुए तिकोनिया चौराहे तक रैली निकाली। तिकोनिया चौराहे पर सभा में डा. पीएस बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। अभाविप प्रदेश मंत्री रोहित ओझा

ओड़िसा की राजधानी **भुवनेश्वर** में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर नागरिकता संशोधन एक्ट का समर्थन किया। सीएए और नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजंस (NRC) के समर्थन में करीब 200 छात्रों और परिषद कार्यकर्ताओं ने उत्कल विश्वविद्यालय से मास्टर कैंटीन तक बाइक रैली निकाली। बाद में, लगभग 600 छात्र और युवा विद्यार्थी परिषद द्वारा महात्मा गांधी मार्ग पर आयोजित तिरंगा रैली में शामिल हुए, जिन्होंने सीएए को अपना समर्थन दिया। परिषद के वक्ताओं ने कहा कि अधिकांश लोग इस अधिनियम के समर्थन में हैं जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक रूप से सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देना है। हर कोई सीएए का समर्थन कर रहा है। केवल कुछ लोगों का एक वर्ग, निहित स्वार्थ वाले, झूठ फैला रहे हैं कि यह अधिनियम देश में मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करेगा और इस अधिनियम के बारे में एक गलत आख्यान स्थापित करने की कोशिश करेगा। इसी तरह गुजरात की राजधानी **अहमदाबाद** में भी छात्रों ने समर्थन मार्च निकालकर ना.सं.एक्ट का समर्थन किया और उपस्थित जनसमूह को समझाने की कोशिश की कि यह एक्ट किसी भी तरह से भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस एक्ट के तहत लोगों को नागरिकता दी जा रही न कि छिनी जा रही है। वहीं **पुणे** (महाराष्ट्र) में धारी, वारजे, सहकार नगर, मॉडल कॉलोनी, बानेर और बावन के स्थानीय लोगों ने एक मानव श्रृंखला बनाई, जो बाल गंधर्व चौक से शुरू होकर गरवारे फ्लाईओवर तक थी। इस मानव श्रृखंला में परिषद के कार्यकर्ता भी थे। डेक्कन में रहने वाले एडवोकेट एएम सुतावने ने कहा, यह सब करते हुए, अन्य देशों के अल्पसंख्यकों को संघर्ष करना पड़ा। इसके विपरीत, भारत में अल्पसंख्यकों ने सभी सुविधाओं का आनंद लिया है। कई भारतीय हैं, जो भारत वापस आ गए, लेकिन उन्हें नागरिकता का दर्जा नहीं है। सीएए से इन लोगों को फायदा होगा।

केरल : नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में संगोष्ठी कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं पर एसएफआई का हमला

देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में डींगे हांकने वाले वामपंथी संगठनों का असली चरित्र उस वक्त उजागर हो गया जब नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में संगोष्ठी कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया, एसएफआई के हमले की वीडियो देश भर में वायरल हो रहा है

दरअसल, अभाविप कार्यकर्ता केरल के त्रिशूर में केरला वर्मा कॉलेज में छात्रों को इस एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए एक सेमिनार में पहुंचे थे। उस दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। वायरल वीडियो में साथ देखा जा सकता है कि एसएफआई के कार्यकर्ता अभाविप कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर कॉलेज से बाहर कर रहे हैं। एसएफआई के इस हमले में परिषद के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है।

अनुशासित छात्र संगठन है विद्यार्थी परिषद: मनोहर लाल खट्टर

अभाविप हरियाण के 51 वें प्रांतीय अधिवेशन के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता बेहद अनुशासित और विचारवान है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का राष्ट्र के विकास में बहुमूल्य योगदान है। परिषद के कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं कि राज्य के विकास में हमारा साथ दें। छात्रसंघ चुनाव पर सरकार का रूख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 22 वर्ष बाद 2018 में छात्रसंघ चुनाव करवाये गए थे। इसमें लिंगदोह की रिपोर्ट भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ये वादा करता हूं कि जब सभी छात्र संगठनों में अभाविप की तर्ज पर अनुशासन और विचार नजर आ जाएगा तो प्रत्यक्ष चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं है।

प्रदर्शनी के उदघाटन पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि जब भी देश विरोधी हरकत होती है, परिषद सकारात्मक सोच के साथ काम करता है। लोगों के लिए संघर्ष कर समस्या को समाधान तक पहुंचाता है। युवा अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं बनें, मगर राष्ट्र व कुछ समाज के लिए भी जरूर कुछ करें। राष्ट्र का नाम व समाज में परिजनों का मस्तक ऊंचा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं, वे ऐसा क्यों और किसके लिए कर रहे हैं। उन्हें पहले इसे समझने की जरूरत है।

शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य पर पारित हुए प्रस्ताव

रोहतक में संपन्न हुए हरियाणा प्रांतीय अधिवेशन में राज्य की शिक्षा और सामाजिक परिदृश्य पर गहन मंथन कर दो प्रस्ताव पारित किया गया। पहला प्रस्ताव हरियाणा के वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर था जबकि दूसरा प्रस्ताव हरियाणा के सामाजिक परिदृश्य को ध्यान रखकर पारित किया गया। पहले प्रस्ताव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हरियाणा नें नए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय खोलने (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में), प्राध्यापकों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार का अभिनंदन करते हुए मांग की है कि सरकार के द्वारा अनेक कल्याणाकारी योजना लाने के बावजूद प्रदेश में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। राज्य के शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त कोष का अभाव है। अभाविप के लंबे संघर्ष के बाद राज्य में छात्र संघ चुनाव हुए लेकिन परिषद का यह मानना है छात्रसंघ चुनावों को प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाया जाय। राज्य की बेरोजगारी को दूर करने के लिए दूरगामी योजना बनाई जाय। हरियाणा खेलों का प्रदेश है हरियाणा के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है। वहीं दूसरे प्रस्ताव में हरियाणा की सामाजिक परिदृश्य में साकारात्मक बदलाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, बढ़ता हुआ लिंगानुपात, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के कदम का स्वागत करते हुए प्रदेश में महिला उत्पीड़न के बढ़ते हुए सामाजिक अपराध, पर्यावरण प्रदूषण, नशा और बढ़ते हुए वृद्धाश्रम पर विद्यार्थी परिषद ने चिंता व्यक्त की है। अभाविप, हरियाणा के प्रांतीय अधिवेशन के बारे में जानकारी देते हुए प्रांत कार्यालय मंत्री करण ने कहा कि परिषद का 51वां प्रांतीय अधिवेशन 28 -30 दिसंबर 2019 को रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। तीन दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन का उदघाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र धीमान आदि ने संयुक्त रूप से किया। अधिवेशन में परिषद की विकास यात्रा के विविध आयाम पर पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, परिसर कार्य और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, परिषद कार्यपद्धति की प्रांसगिकता पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल का भाषण हुआ। अधिवेशन के समापन सत्र प्रांत संगठन मंत्री श्याम सिंह राजावत ने संबोधित किया। अधिवेशन में हरियाणा प्रांत के सभी जिले से 618 प्रतिनिधि उपस्थित थे जिसमें 492 छात्र, 90 छात्राएं और 36 शिक्षक शामिल हैं।

युवा शक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र हित में करें : सोम प्रकाश

पंजाब प्रांत के प्रांतीय अधिवेशन के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि युवा शक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्रिहत में करें। उन्होंने कहा कि युवा अपने आफ को पहचाने, अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को पहचान कर राष्ट्रहित में इसका उपयोग करें। श्री सोम ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ही एक मात्र ऐसा संगठन है जो शिक्षा के प्रति सजग और सकल सहयोग कर रहा है। पंजाब को युवाओं से आशा है कि युवाओं को बिना पतवार नाव नहीं बनना चाहिए।

वहीं अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने हुए कहा कि समाज जीवन में विभिन्न दायित्व का निर्वहन कर रहे कार्यकर्ताओं के निर्माण का कार्य अभाविप ने किया है। विशिष्ट कार्य पद्धति से अभाविप आज देश भर में कार्य कर रही है है। विभिन्न परिस्थितियों में समय - समय पर अभाविप ने समस्याओं के समाधान में अपनी महती भूमिका निभाई है। वहीं वहीं किंदर गोयल ने कहा कि अभाविप समाज में एवं छात्रों के बीच अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पंजाब प्रांत के 51 वें प्रांत अधिवेशन का आयोजन लुधियाना के शहीद सुखदेव नगर में 24 - 26 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ। अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री राहुल शर्मा ने बताया कि 51 वें प्रांत अधिवेशन में प्रांत भर से कुल 199 प्रतिनिधि सहभागी हुए, जिसमें 159 छात्र, 32 छात्रा एवं 08 प्राध्यापक हैं। प्रांत अधिवेशन का उदघाटन केन्द्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश, अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर एवं गायक किंदर गोयल ने किया।

पंजाब की शिक्षा व्यवस्था और प्रदेश के वर्तमान स्थिति में सुधार करने की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांतीय अधिवेशन में पंजाब की शिक्षा व्यवस्था और इसके दयनीय हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने, विद्यालय - महाविद्यालयों में ठेके की भर्ती रोकने, शैक्षिक संस्थानों में खाली पदों को अविलंब भरने, गरीब/मेधावी विद्यार्थियों के समस्याओं को निदान करने, पाठयक्रम में भारतीयता एवं प्रादेशिक इतिहास को शामिल करने, निजी संस्थानों के मनमानी को रोकने, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की सेवा विस्तार को रोकने, यूजी पाठ्यक्रम में सेमेस्टर प्रणाली को हटाने की मांग शामिल है। वहीं दूसरा प्रस्ताव पंजाब के वर्तमान परिदृश्य पर है। इस प्रस्ताव में अभाविप ने पंजाब सरकार शस्त्र अधिनियम 1959 के संशोधन को मंजूरी देने, राजनेता - गैंगस्टर गठबंधन की उचित जांच कर उस पर कार्रवाई करने, बलात्कार मामलों के निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए किसानों को सहायता प्रदान करने, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने, राज्य ड्रग्स(निवारण) आयोग बनाने, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने, 21 फरवरी को राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने, गानों के लिए सेंसर बोर्ड बनाने, पीपीएससी परीक्षा का शुल्क कम करने, कृषि विधियों और फसलों का विविधीकरण और वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से भूजल स्तर को और अधिक बढ़ाने के प्रयास किये जाने की मांग की गई है।

भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति हार्वड और ऑक्सफोर्ड के लिए उदाहरण : चौहान

बलिया में आयोजित अभाविप **गोरक्ष प्रांत** के प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति वर्तमान समय में हॉवर्ड और ऑक्सफोर्ड के लिए उदाहरण बना हुआ है। तक्षशिला, विक्रमशिला एवं नालंदा की शिक्षा पद्धति से पूरी दुनिया ने अपनी शिक्षा पद्धति लिया है। श्री चौहान भारत के शैक्षिक परिवर्तन की दिशा में हमारी भूमिका विषय पर बोल रहे थे।

परिषद की कार्यपद्धति और प्रासंगिकता विषय पर अपना मनोगत रखते हुए अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय सह - संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन ने कहा कि भारत एक युवा देश है, देश की सुरक्षा युवाओं पर निर्भर है। अभाविप के नाते नहीं बल्कि संपूर्ण युवा शक्ति को देश के परिवर्तन, समर्थ समृद्धि के लिए भारतीय विचारधारा के लिए कार्य करना चाहिए। बता दें कि गोरक्ष प्रांत का अधिवेशन 14 -16 दिसंबर को बलिया में संपन्न हुआ, जिसमें प्रांत भर से 800 से अधिक प्रतिनिधि ने सहभाग लिया। इसे मौके पर प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य, प्रदेश का शैक्षिक परिदृश्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदी संरक्षण- वर्तमान में पानी एक गंभीर समस्या पर प्रस्ताव पारित किये गये। ■

क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाली हिंसा के तार आपस में जुड़े हैं?

विश्वविद्यालय को ज्ञानार्जन का केन्द्र कहा जाता है, माना जाता है कि यहां से देश का भविष्य तैयार होता है लेकिन अगर विश्वविद्यालय ही हिंसा का अखाड़ा बन जाय तो क्या कहा जाय ? चाहे घटनाएं कुछ भी घटित हो उसका प्रसार जितनी तेज गति से शैक्षिक परिसरों में होती है उतनी रफ्तार सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण माध्यमों में भी नहीं होता है। आये दिन देखने को मिलता है कि किसी विश्वविद्यालय में हिंसात्मक प्रदर्शन होता है तो कुछेक मिनट के अंदर ही वह देश के अन्य शैक्षिक परिसरों में पहुंच जाता है। पिछले दिनों पीड़ित शरणार्थियों के अधिकारो के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामियां विश्वविद्यालय में हिंसक प्रदर्शन हुआ और उसके तुरंत बाद जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जेएनयू और उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद जैसे शैक्षिक परिसरों में भी उसी अंदाज में हिंसा होना शुरू हो गया। विश्वविद्यालय से निकली हिंसा की आग उसके बाद देश भर में फैल गया, जिस कारण करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या विभिन्न विश्वविद्यालय में होने वाले हिंसात्मक घटनाओं के तार आपस में जुड़े हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय छात्रशक्ति के द्वारा एक परिचर्चा आयोजन किया गया जिसके तहत देश भर के लोगों से राय मांगी गई। प्रस्तुत है कुछ चुनी हुई प्रतिक्रियाएं –

किसी एक विश्वविद्यालय में हिंसक गतिविधियों का किसी अन्य दूसरे विश्वविद्यालयों में फैल जाना, अनायास तो नहीं हो सकता। डिजिटल क्रांति के इस युग में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर इसके प्रसार में सहायक हो रहे हैं। साथ ही सबसे प्रमुख कारण है वैचारिक क्रांति के नाम पर छात्रों को बरगलाने वाले छात्र संगठन जिनका उद्देश्य मात्र हिंसात्मक गतिविधियों के जरिये अपनी ताकत दिखाना भर है। ऐसे छात्र संगठनों की भरमार है, जो एक विश्वविद्यालय या यूं कहें कुछ चन्द मुट्ठी भर लोगों के द्वारा नियंत्रित है। कहने को तो लोग इसे क्रांति का नाम देकर एक दूसरे विश्वविद्यालय के 'साथी' की मदद करते हैं पर उनका एजेंडा विपक्षी पार्टियों के नेताओं के समक्ष अपना ग्राफ बढ़ाने का होता है। 'अंकल छात्र नेताओं' को ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने महारत हासिल है। अपनी राजनैतिक जमीन की तलाश में विपक्षी नेताओं की भी ऐसी हिंसात्मक आंदोलन को बढ़ावा देने में भूमिका कम नहीं है। जेनयू के बाद जामिया, आईएएससी, उस्मानिया की घटनाओं के आपस में तार जुड़े हुए हैं और उसका मुख्य कारण सीधे तौर पर तथाकथित 'क्रांति' की दुहाई देनेवाले छात्र संगठन और उनके 'अंकल छात्र नेता' ही हैं।

- **चिन्मयी दास,** शोध छात्रा (मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार)

देश के कई नामचीन नेता छात्र राजनीति से ही उभरे हैं। शैक्षिक परिसरों में छात्र राजनीति का होना जरूरी है। एआईएसएचई पोर्टल में 993 विश्वविद्यालय, 39931 महाविद्यालय सूचीबद्ध हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जादवपुर जैसे कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर राजनीतिक अशांति पैदा करने के लिए वामपंथी छात्र संगठन हमेशा भारत सरकार के खिलाफ गतिविधियां करते रहते हैं। छात्र एक्टिविजम के नाम ये कैंपस में अराजकता का माहौल तैयार करते हैं और धीरे धीरे यह देश के अन्य भागों में फैलता है। कोई भी विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए न कि हिंसात्मक तरीके से। वाम उदारवादी विचार वाले छात्र कैंपस में गतिविधि का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार को गाली देने, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने बचा है और वे इस भूमिका का अच्छी तरह निभा भी रहे हैं। एक तरफ वो संविधान बचाने की बात हैं वहीं दूसरी खुद ही संवैधानिक मूल्यों को चोट पहुंचाते हैं।

- **प्रीतम पॉल,** अगरतला (त्रिपुरा पश्चिम)

निश्चित रूप से इन विश्वविद्यालयों में होने वाली असामाजिक गतिविधियां किसी न किसी रूप से आपस में जुड़ी हुई हंद। इन सबकी सोच भारत को खंड - खंड करने की है, इनका फंड विदेशों से रुक गया है अब इनकी पूछ लगभग न के बराबर है। इनकी विचारधारा को मानने वाले भी चंद लोग बचे हैं। इन्हें भारतीय सनातन संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। देश में अराजकता का माहौल फैला कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना पर ध्येय है। गलती खुद करते हैं और उसका दोषारोपण किसी अन्य पर करके खुद को पीड़ित के रूप में दिखलाते है, साथ ही भारत सरकार पर एक पक्षीय होने का आरोप भी लगाते हैं। इन विश्वविद्यालयों के गतिविधियों के तार जरूर एक दूसरे से जुड़े अन्यथा चंद घंटों के अंदर दूसरे विश्वविद्यालय में वही नारा, वही राग और उसी स्टाईल में प्रदर्शन कैसे हो सकता है ? सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए साथ ही ऐसे विध्वंसकारी मानसिकता को चिन्हित कर उसका नकाब उतराना चाहिए।

- **ग्रीष्मा त्रिवेदी,** शोध छात्रा (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश)

परिषद गतिविधियां

भुवनेश्वर : राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित प्रतिभा संगम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुती देती छात्राएं

हिमाचल प्रदेश : जरूरतमंदों के लिए वस्त्र एकत्रित करते अभाविप प्रकल्प सेवार्थ विद्यार्थी के कार्यकर्ता

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 JANUARY, 2020
DATE OF PUBLISHING: 8 JANUARY, 2020

POSTAL REGD. NO.: DL(C)-11/1409/2020-2022
POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI

सीएए: देशव्यापी समर्थन मार्च